वर्ष 12 • अंक 274 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शनिवार 4 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 4

अब अस्पतालों की रेटिंग की बारी

गौतम अदाणी ▶▶ पृष्ठ 2

अदाणी ने कृष्णापत्तनम बंदरगाह में हिस्सा खरीदा

डॉलर रु. 71.80 ▲ 40 पैसे | यूरो रु. 79.90 (अपरिवर्तित) | सोना (10ग्राम) रु 39931 ▲ 873 रुपये | सेंसेक्स 41464.6.60 ▼ 162.00 | निफ्टी 12226.70 ▼ 55.50 | निफ्टी फ्यूचर्स 12256.50 ▲ 29.80 | ब्रेंट क्रूड 69.20 डॉलर ▲ 2.60 डॉलर

एक नज़र

31 जनवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र

सरकार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू करने पर विचार कर रही है और आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति की सिफारिश के बाद सरकार बजट सत्र की तिथि अधिसूचित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुआई वाली इस समिति की जल्दी बैठक हो सकती है। बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और उसी दिन आर्थिक समीक्षा पेश की जा सकती है। यह सत्र अप्रैल तक जारी रहने की उम्मीद है। अमूमन इस दौरान एक महीने का सत्रावकाश होता है।

एनवाईटी की खबर के बाद सतर्कता बढ़ा रही ओयो

ओयो ने शुक्रवार को न्यूयार्क टाइम्स की खबर की प्रतिक्रिया में कहा कि वह कंपनी को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। प्रकाशित खबर में कंपनी की व्यावसायिक प्रणालियां संदिग्ध होने का आरोप लगाया गया था। ओयो ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कि हमारे मूल्यों को दुनिया भर में मौजूद हजारों कर्मचारियों द्वारा सराहा जाए। पृष्ठ 2

जुर्माना दे आय कर अपराध निपटाने की तिथि बढ़ी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकरदाताओं को जुर्माना देकर अपने कर अपराध का निपटान करने की योजना की समयसीमा 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। यह अवसर एक बार के लिए है। इससे पहले यह सुविधा 31 दिसंबर 2019 तक खुली थी। सीबीडीटी ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की क्षेत्रीय शाखाओं और अन्य संगठनों की सलाह पर समयसीमा बढ़ाने का यह निर्णय लिया गया है।

उड्डयन घोटाले में चिदंबरम से ईडी ने की पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संप्रग के शासनकाल में हुईं कथित उड्डयन संबंधी वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ की। अधिकारियों के मुताबिक चिदंबरम से ईडी कार्यालय में करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई। धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। मामला करोड़ों रुपये के कथित उड्डयन घोटाले और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए हवाई स्लॉट निर्धारित करने में अनियमितताओं के चलते एयर इंडिया को हुए कथित नुकसान से जुड़ा है।

आरओसी की याचिका पर एनसीएलएटी में सुनवाई पूरी

नैशनल कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को कंपनी पंजीयक, मुंबई की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली। यह याचिका टाटा संस बनाम साइरस मिस्त्री मामले में फैसले में प्रतिकूल टिप्पणी हटाने के लिए दाखिल की गई है। दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह अपना फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन स्पष्टीकरण जारी करेगा ताकि आरओसी की छवि धूमिल न हो। पंचाट ने 18 दिसंबर के आदेश में आरओसी पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा था कि टाटा संस ने आरओसी के सहयोग से हड़बड़ी में खुद को सार्वजनिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी के रूप में तब्दील कर दिया, जो अवैध है। पृष्ठ 2

अमेरिकी हमले से बाजार फिसले

बगदाद में अमेरिकी हमले में ईरान के एक शीर्ष कमांडर की मौत से खाड़ी में तनाव का साया

एजेंसियां
नई दिल्ली, 3 जनवरी

इराक में अमेरिकी कार्रवाई में ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर के मारे जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका से आज कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल करीब 3 डॉलर की उछाल आई और सोना, येन तथा सुरक्षित समझे जाने वाले बॉन्ड भी चढ़ गए।

कुद्स फोर्स के प्रमुख और ईरान के मेजर जरनल कासिम सुलेमानी की मौत और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की बदले की धमकी से दुनिया भर के कारोबारी दहशत में दिखे। ब्रेंट कच्चा तेल 4.5 फीसदी की बढ़त के साथ 69.20 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया जो सितंबर के बाद उसका उच्चतम स्तर है। दुनिया भर के तेल बाजारों में इसका असर देखा गया। यूरोप का स्टॉक्स 600 और वाल स्ट्रीट वायदा में करीब एक फीसदी की गिरावट आई। येन डॉलर के मुकाबले आधा फीसदी चढ़कर दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह स्विस फ्रैंक भी यूरो के मुकाबले सितंबर के बाद उच्चतम स्तर पर चढ़ गया।

सुलेमानी बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अमेरिकी हमले में मारे गए। इससे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस हमले के बाद ईरान और आसपास के क्षेत्रों में संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। निवेशकों को आशंका है कि इस संघर्ष का असर पश्चिम एशिया में कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में भूराजनीतिक टकराव बढ़ने के जोखिम के बीच भारतीय शेयर बाजारों में बिकवाली का जोर रहा और प्रमुख शेयर सूचकांक गिरावट में रहे।

वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आई। निवेशकों ने इसके बाद सोना तथा जापानी येन जैसे सुरक्षित निवेश को तरजीह दी। एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट, हॉन्ग कॉन्ग का हैंग सेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि खुद राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सुलेमानी को मारने के आदेश दिए थे। सुलेमानी की मौत के बाद ट्रंप ने बिना किसी विस्तृत जानकारी के अमेरिकी झंडा ट्वीट किया था। खामेनी ने इसका कड़ा प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया और देशभर में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि ईरान और क्षेत्र के आजाद देश सुलेमानी की मौत का बदला अमेरिका से लेंगे।

इस घटनाक्रम के बाद हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने इराक में मौजूद अमेरिकी नागरिकों से जल्द से जल्द देश छोड़ने के लिए कहा है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यह एक दुस्साहिक कदम है, लेकिन इससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। चीनी ने कहा कि वह हमेशा से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग का विरोध करता रहा है।

ईरानी कमांडर की मौत के बाद तेहरान में प्रदर्शन करते लोग *फोटो: रॉयटर्स*

खौफ में बाजार

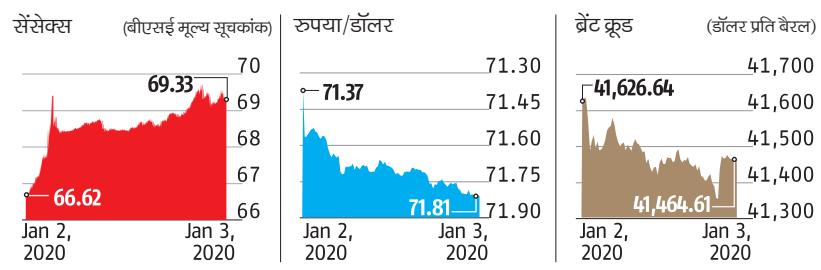

भारत पर असर

अमेरिकी हमले में ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 4.4 फीसदी की तेजी आई और यह शुक्रवार को 69.16 डॉलर प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। पृष्ठ 14

बीमारी से नौकरी जाने पर भी मुआवजा

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 में ऐसे कामगारों को मुआवजे का प्रावधान

सोमेश झा
नई दिल्ली, 3 जनवरी

जल्द ही कंपनियों को उन कामगारों को भी मुआवजा देना पड़ेगा जिन्हें लंबी बीमारी के कारण नौकरी से निकाला जाएगा। मौजूदा नियम के मुताबिक इस तरह के कामगारों के लिए मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 में ऐसे कामगारों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने इस विधेयक को पिछले साल दिसंबर में श्रम पर संसद की स्थायी समिति के हवाले किया था।

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक के जरिये तीन श्रम कानूनों को साथ मिलाया जाएगा। इनमें ट्रेड यूनियंस ऐक्ट, 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) ऐक्ट, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 शामिल हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के मुताबिक छंटनी करने पर नियोक्ताओं को कामगारों को मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्हें मुआवजा देने में छूट मिली है जिनमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है। साथ ही अगर किसी कामगार को लंबे समय तक बीमार रहने के कारण नौकरी से निकाला जाता है तो वह मुआवजा पाने का हकदार नहीं है। लेकिन दिसंबर में लोक सभा में पेश किए गए औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 में इस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ के महासचिव वृजेश उपाध्याय ने कहा, 'बीमारी कामगारों के वश में नहीं है। कई ऐसे मामले थे जिनमें नियोक्ताओं ने लंबी बीमारी के कारण कामगारों की नौकरी खत्म कर दी। कभी-कभार इससे औद्योगिक विवाद भी पैदा होते हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में कामगार उचित मंच पर अपना मामला नहीं ले जा पाते हैं। सरकार का यह प्रस्ताव कामगारों के पक्ष में स्वागतयोग्य कदम है।'

नियोक्ताओं को किसी कामगार को नौकरी से निकालने से पहले उसे एक महीने का नोटिस और मुआवजा देना पड़ता है। इसमें हर साल श्रमिक के 15 दिनों के वेतन का भुगतान भी शामिल होता है।

साथ ही सरकार ने ऐसे कामगारों को छंटनी से बचाने के लिए भी प्रावधान किया है जिन्हें एक निश्चित समय के लिए नौकरी पर रखा गया है। हालांकि इस विधेयक के जरिये निश्चित अवधि के लिए रोजगार को कानूनी मान्यता मिल जाएगी लेकिन अगर कंपनियों ऐसे कामगारों को उनकी नौकरी की निश्चित अवधि खत्म होने से पहले निकालती हैं तो उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा।

विधेयक के मुताबिक अगर किसी कामगार के अनुबंध की अवधि खत्म होने के बाद उसे निकाला जाता है तो इसे छंटनी नहीं माना जाएगा। यानी ऐसे कामगार मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'अगर निश्चित अवधि के अनुबंध वाले कामगारों को पहले निकाला जाता है तो कानून के मुताबिक उन्हें मुआवजा देना होगा।'

विधेयक में निश्चित अवधि से संबंधि रोजगार वाले हिस्से में कहा गया है कि ऐसे कामगारों को कंपनी में काम करने वाले नियमित कामगारों के समान सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। मौजूदा प्रणाली में कंपनियां ठेकेदारों के जरिये कामगारों की नियुक्तियां करती हैं और उनका कहना है यह उनके लिए फायदेमंद होता है। निश्चित अवधि की रोजगार प्रणाली के जरिये कंपनियां अनुबंध पर सीधे ऐसे कामगारों की नियुक्ति कर पाएंगी।

...श्रम सुधार

- ऐसे कामगारों को अभी नहीं मिलता है मुआवजा
- दिसंबर में स्थायी समिति को भेजा गया था विधेयक
- इसमें तीन श्रम कानूनों का होगा विलय

रतन टाटा भी पहुंचे उच्चतम न्यायालय

देव चटर्जी
मुंबई, 3 जनवरी

टाटा संस के बाद अब टाटा समूह के संरक्षक रतन टाटा, टाटा ट्रस्ट्स के न्यासी वेणु श्रीनिवासन और टाटा टेलीसर्विसेस ने भी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। टाटा ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के रूप में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। एनसीएलएटी ने टाटा और ट्रस्ट के दूसरे नामित सदस्यों को टाटा संस के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेने का भी आदेश दिया था।

टाटा ने कहा कि 18 दिसंबर को आए एनसीएलएटी के आदेश में उनकी, एन ए सूनावाला (टाटा ट्रस्ट्स के पूर्व न्यासी) और नितिन नोहरिया (ट्रस्ट्स द्वारा नामित निदेशक) की कथित तौर पर अधिकारियों के दुरुपयोग के लिए खिंचाई की गई है। टाटा समूह के संरक्षक ने अपनी याचिका में कहा कि एनसीएलएटी का आदेश अनुचित, गलत, पूरे मामले के विपरीत है, जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

रतन टाटा और टाटा संस की याचिकाओं का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सोमवार को किया जाएगा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश सुनवाई की तिथि और न्यायाधीशों के पीठ के बारे में निर्णय लेंगे। टाटा टेलीसर्विसेस ने याचिका में कहा कि कंपनी एनसीएलटी या एनसीएलएटी में पहुंचे विवाद में पक्षकार नहीं थी, बावजूद इसके उसे मिस्त्री को निदेशकमंडल में शामिल करने के लिए कहा गया है।

टाटा ट्रस्ट्स की याचिका में कहा गया है कि टाटा संस के अनुच्छेदों में अनुच्छेद 75 प्रताड़ित करने वाला नहीं है और न ही इसे ही कंपनी की मूल याचिका में चुनौती भी नहीं दी गई थी। याचिका के अनुसार टाटा संस का पब्लिक से प्राइवेट में तब्दील किए जाने को एनसीएलएटी द्वारा अवैध बताना अनुचित है। टाटा और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के बीच तनातनी के बाद टाटा संस के बोर्ड ने मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में बर्खास्त कर दिया था। शेष पृष्ठ 3

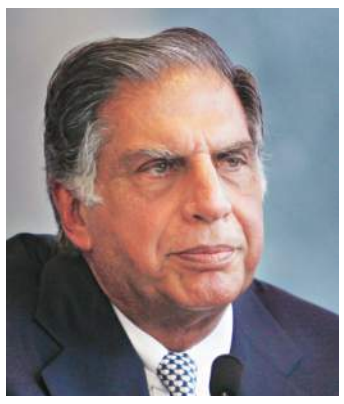

टाटा ने कहा...

- टाटा ट्रस्टी चेयरमैन के तौर पर नहीं किया अधिकारों का दुरुपयोग
- साइरस मिस्त्री के खिलाफ नहीं रची साजिश
- मिस्त्री ने एसपी समूह के कारोबार से स्वयं को नहीं किया अलग
- मिस्त्री के कार्यकाल में टाटा समूह की कंपनियों के निदेशक किए गए अलग-थलग
- डोकोमो को भुगतान से मिस्त्री के पलटने से टाटा समूह की साख हुई धूमिल

अनधिकृत कॉलोनियों में मकानों की रजिस्ट्री शुरू

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जनवरी

- केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने **20** लोगों को सौंपे रजिस्ट्री के कागज
- अब तक मालिकाना हक के लिए 57 हजार कर चुके हैं आवेदन

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में मकानों की रजिस्ट्री शुक्रवार से शुरू हो गई है। इससे दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय आवास व शहरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप पुरी ने कुछ लोगों को रजिस्ट्री के कागज सौंपकर इसकी शुरूआत की गई। केंद्र सरकार द्वारा रजिस्ट्री की इस शुरूआत को दिल्ली सरकार ने धोखा बताते हुए इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

पुरी ने रजिस्ट्री की शुरूआत करने के बाद कहा, 'अनधिकृत कॉलोनियों के लिए कानून लाने के बाद हमने अपने 20 बहन-भाइयों को उनके घर की रजिस्ट्री के कागज और कन्वेयंस डीड सौंप दिए।' संपत्ति का पहला पंजीकरण प्रमाणपत्र समयपुर बादली स्थित सूरज पार्क कालोनी की पिंकी शर्मा को दिया गया। पुरी ने बताया कि पहले 20 लाभार्थी सूरज पार्क और राजा विहार कॉलोनियों के हैं। इन लोगों ने 18 दिसंबर को संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया था। इसके लिए 16 दिसंबर को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पुरी ने बताया कि अब तक 57 हजार आवेदन आ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे आवेदकों के दस्तावेजों की जांच और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती जाएगी, वैसे मालिकाना हक और पंजीकरण प्रमाणपत्र लाभार्थियों को मिलते जाएंगे।

मुरुगप्पा परिवार में गहराया घमासान

पवन लाल
मुंबई, 3 जनवरी

चेन्नई स्थित मुरुगप्पा ग्रुप के प्रवर्तकों का आपसी विवाद गहराता ही जा रहा है। मुरुगप्पा ग्रुप के पूर्व वरिष्ठतम सदस्य और संरक्षक एमवी मुरुगप्पन की दो वर्ष पहले मृत्यु के बाद परिसंपत्ति निपटान का मामला अब तक नहीं सुलझ पाया है। एमवी मुरुगप्पन कार्बोरंडम यूनिवर्सल के चेयरमैन और समूह की परोपकारी संस्था के न्यासी भी थे।

मुरुगप्पन की मौत के बाद उनकी 8.15 प्रतिशत हिस्सेदारी के वारिसों में उनकी दो पुत्रियों में सबसे बड़ी एवं पेशे से तकनीकी सलाहकार वल्ली अरुणाचलम भी अपनी माता एव वी वल्ली मुरुगप्पन के साथ शामिल थीं। अरुणाचलम ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि उन्हें जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है, लेकिन जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो उन्हें दूसरे विकल्प आजमाने होंगे। उन्होंने कहा, 'निदेशकमंडल में महिलाओं को जगह दिलाने की यह लड़ाई उन दूसरी महिलाओं के लिए स्थितियां आसान कर देगी, जिन्हें भेदभाव से गुजरना पड़ रहा है।' मुरुगप्पन ग्रुप की इंजीनियरिंग, चीनी, कृषि उत्पाद, प्लांटेशन, कन्फेक्शनरी बायो-उत्पाद, रसायन, बीमा एवं वित्तीय सेवाओं आदि कारोबारों में मौजूदगी है। यह नौ विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों का भी परिचालन करता है, जिनका संयुक्त कारोबार 36,000 करोड़ रुपये से अधिक और बाजार पूंजीकरण 69,000 करोड़ रुपये है। समूह के हितों पर इसकी एक कंपनी अंबाडी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का नियंत्रण है। अरुणाचलम का कहना है कि यह एक प्राइवेट कंपनी है, जिसके निदेशक मंडल में एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं है। अरुणाचलम का तर्क है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद कंपनी का मौजूदा प्रबंधन एवं उनके चाचा एमवी सुबैया, जो परिवार में वरिष्ठतम हैं, और उन्होंने विरासत को लेकर दो संभावित उपायों पर विचार किया था। इन दो विकल्पों में एक विकल्प दिवंगत पिता की हिस्सेदारी उचित बाजार मूल्य पर खरीदना और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति देना या निदेशक मंडल में उन्हें जगह देना था।

हालांकि समूह ने किसी भी विकल्प पर सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा, 'अब कंपनी में एक सबसे बड़े शेयरधारक की हैसियत से कंपनी के संचालन को लेकर हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है। शेष पृष्ठ 14

वल्ली अरुणाचलम

वल्ली अरुणाचलम का तर्क

- पुरुष की तरह महिला वारिस को भी दिए जाएं समान अवसर
- समूह की निवेश कंपनी अंबाडी इन्वेस्टमेंट्स में अरुणाचलम को दी जाए जगह
- महिलाओं के मुकाबले पुरुष काफी पहले कारोबारों में रखते हैं कदम
- मुरुगप्पन समूह में तीन पीढ़ियों में जन्मीं **13** पुत्रियों में किसी को भी प्रबंधन में नहीं मिला स्थान

व्यापार गोष्ठी

नए साल से आर्थिक एवं कारोबारी उम्मीदें ?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें gosthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या अमेरिकी हमले के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ेगा तनाव

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या अगले वित्त वर्ष में सुधर जाएगा एफएमसीजी कंपनियों का कारोबार	हां	66.67%
	नहीं	33.33%

संक्षेप में

एनएसई के लिए एसबीआई ने मांगी बोली

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पूंजी जुटाने की कोशिशों के तहत एनएसई में अपनी 1.01 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। एसबीआई ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। एनएसई में एसबीआई की 5.19 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बैंक ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, 'एसबीआई एनएसई इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों में से एक है और प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के जरिये 1.0101 प्रतिशत हिस्सेदारी यानी 50 लाख शेयर बेचने की योजना है।' बैंक ने कहा कि तय प्रारूप में न्यूनतम 10 लाख शेयरों के लिये बोली लगाई जा सकती है। बोली लगाने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। *भाषा*

रेनो की बिक्री दिसंबर में 64.73 प्रतिशत बढ़ी

रेनो इंडिया की बिक्री दिसंबर में 64.73 प्रतिशत बढ़कर 11,964 इकाई हो गई। कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उसने कहा कि पिछले साल दिसंबर में उसने 7,263 वाहनों की बिक्री की थी। कंपनी ने कहा कि उसके नये मॉडल – ट्राइबर, क्विड और डस्टर की बिक्री 2019 में 7.8 प्रतिशत बढ़कर 88,869 इकाई हो गई। कंपनी ने कहा कि सात सीटों वाले बहुद्देश्यीय वाहन ट्राइबर को अगस्त 2019 में बाजार में उतारे जाने के बाद से इसकी 24,142 इकाइयां बेची जा चुकी हैं। *भाषा*

अदाणी ने कृष्णापत्तनम बंदरगाह खरीदा

अदिति दिवेकर
मुंबई, 3 जनवरी

देश की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह ऑपरेटरों में शामिल अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने आज घोषणा की कि वह 13,572 करोड़ रुपये की उद्यम वैल्यू में आंध्र प्रदेश स्थित कृष्णापत्तनम पोर्ट कंपनी में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी।

गौतम अदाणी के नेतृत्व वाली कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि प्रस्तावित अधिग्रहण अब तक एपीएसईजेड का सबसे बड़ा सौदा है और इसका वित्त पोषण आंतरिक स्रोतों और मौजूदा नकदी के जरिये किया जाएगा। एपीएसईजेड के मुख्य कार्याधिकारी करण अदाणी के हवाले से कहा गया है, 'यह अधिग्रहण वित्त वर्ष 2025 तक 40 करोड़ टन की माल ढुलाई क्षमता का प्रबंधन करने के हमारे उद्देश्य को मजबूत बनाएगा। श्रेष्ठ स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए यह अधिग्रहण हमारी बाजार भागीदारी मौजूदा 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने में मददगार साबित होगा।'

एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा गया है कि चूंकि यह अधिग्रहण नियामकीय मंजूरियों के अधीन है, लेकिन 120 दिन के अंदर यह सौदा पूरा हो जाने की संभावना है।

कंपनी का कहना है कि एपीएसईजेड की ऋण स्थिति में इस सौदे से बदलाव आने की आशंका नहीं है और उसका शुद्ध डेट/एबिटा (वित्त वर्ष 2021 में कृष्णापत्तनम पोर्ट समेत) 3.2 गुना पर रहने का अनुमान है, जो अधिग्रहण-पूर्व वित्त वर्ष 2019 में 3.1 गुना के शुद्ध डेट/एबिटा के अनुरूप है।

सीवीआर ग्रुप-प्रवर्तित कृष्णापत्तनम पोर्ट विभिन्न तरह के माल का प्रबंधन करने वाला प्रमुख बंदरगाह है और वित्त वर्ष 2019 में उसने 5.4 करोड़ टन क्षमता का प्रबंधन किया।

कंपनी का कहना है, 'हमें उम्मीद है कि बंदरगाह लगभग 7 साल में 10 करोड़ टन की क्षमता के प्रबंधन में सक्षम होगा और चार साल में इसका एबिटा दोगुना हो जाएगा।'

इस अधिग्रहण के जरिये, कंपनी भारत के पूर्वी तट में अपनी स्थिति मजबूत बनाएगी। अदाणी पोर्ट्स एन्नोर और कट्टुपल्ली (तमिलनाडु), विजाग (आंध्र प्रदेश), और धामरा (ओडिशा) बंदरगाहों और पूर्वी तट पर टर्मिनलों का परिचालन पहले से ही कर रही है।

अगले कुछ वर्षों के दौरान कंपनी की क्षमता वृद्धि योजनाओं में विलय एवं अधिग्रहण के जरिये विकास का विकल्प शामिल होगा। अदाणी पोर्ट्स का शुद्ध डेट/एबिटा पिछले कुछ वर्षों से उतार-चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन यह मौजूदा समय में अच्छी स्थिति में है जिससे कई और सौदों के लिए संभावना बनी हुई है।

पिछले सप्ताह, अदाणी पोर्ट्स ने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में 40.25 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदकर कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सेगमेंट में प्रवेश किया। यह हिस्सेदारी कंपनी ने गेटवे डिस्ट्रिपार्क्स लिमिटेड से खरीदी है।

ताजा अधिग्रहण के बाद, ब्रोकर यह अनुमान लगा रहे हैं कि कंपनी एनसीएलटी में शामिल दिघी पोर्ट पर नजर रखेगी। यदि दिघी पोर्ट का सौदा होता है तो इससे अदाणी समूह महाराष्ट्र में पैर जमाने में सफल हो जाएगा।

अदाणी पोर्ट्स का विस्तार पर जोर

- विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी अब एनसीएलटी में शामिल दिघी पोर्ट पर ध्यान दे सकती है
- इस अधिग्रहण से अदाणी पोर्ट्स को बाजार भागीदारी बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने में मदद मिलेगी

अतिरिक्त नकदी 4 लाख करोड़ रुपये के पार

अनूप रॉय
मुंबई, 3 जनवरी

बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी गुरुवार को 4 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई। शुक्रवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिलती है। सरकार ने 2003 में जारी किए गए अपने 61,000 करोड़ रुपये के बॉन्डों को भुनाया है।

सरकार सोमवार को नकदी प्रबंधन बिल के जरिये 30,000 करोड़ रुपये की 70 दिन की पूंजी जुटाएगी। आरबीआई ने 4.15 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी खपाने के लिए शुक्रवार को 15,000 करोड़ रुपये की 63-दिन की रिवर्स रीपो नीलामी की।

दिसंबर में व्यवस्था में नकदी 2-2.5 लाख करोड़ रुपये के आसपास थी और 1 जनवरी को यह 3 लाख करोड़ रुपये पर थी। नकदी को लेकर पिछली बार इस तरह की स्थिति 2016 के अंत में नोटबंदी के बाद और 2017 के शुरू में दर्ज की गई थी।

हालांकि नोटबंदी के समय के विपरीत,इस बार केंद्रीय बैंक अतिरिक्त नकदी को खपाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नोटबंदी के दौरान, केंद्रीय बैंक के पास सिर्फ लगभग 7 लाख करोड़ रुपये की बॉन्ड पूंजी थी। हाल के समय में केंद्रीय बैंक ने अपनी बॉन्ड खरीदारी को मजबूत बनाया है। आरबीआई को बैंकों से ली गई रकम के बदले बॉन्ड देने होते हैं।

> व्यवस्था में नकदी दिसंबर में 2-2.5 लाख करोड़ रुपये के आसपास और 1 जनवरी को यह 3 लाख करोड़ रुपये पर थी

लेकिन बॉन्ड डीलरों को कुछ मामूली चिंताओं को छोड़कर ज्यादा नकदी अधिशेष से व्यवस्था पर दबाव पड़ने की आशंका नहीं दिख रही है। बदरीश कुल्हाली ने कहा, 'मौजूदा मामले में, ऐसा नहीं लग रहा है कि अतिरिक्त नकदी की वजह से मुद्रास्फीति में तेजी आएगी। अर्थव्यवस्था में मांग अभी भी काफी कमजोर है। अतिरिक्त नकदी से दरें रीपों दरों पर या इससे कुछ नीचे बनी रहेंगी।'

यदि व्यवस्था में लंबे समय तक पर्याप्त नकदी बनी रहे तो क्या हो सकता है? इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के सहायक निदेशक सौम्यजीत नियोगी ने कहा, 'पर्याप्त नकदी पिछले एक साल में व्यवस्थागत जोखिम के समायोजन में मददगार रही है।' नियोगी ने कहा, 'समस्या ऋण के लिए कमजोर मांग की वजह से है। व्यवस्था सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में केंद्रीय बैंक पर अधिक निर्भर हो रही है।'

आरबीआई बॉन्ड प्रतिफल को बाजार ताकतों पर छोड़ने के बजाय इसे प्रभावित करने की भी कोशिश कर रहा है। इसका कारण ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के जरिये अल्पावधि बॉन्डों और लंबी अवधि के प्रतिफल के बीच अंतर को कम करना हो सकता है, लेकिन बाजार का मानना है कि केंद्रीय बैंक कम दर पर अतिरिक्त उधारी के संदर्भ सरकार के लिए आधार तैयार कर रहा है।

कुल्हाली ने कहा, 'अतिरिक्त नकदी जुटाने के लिए आरबीआई द्वारा अल्पावधि में कोई कदम उठाए जाने की संभावना नहीं है। विशेष ओएमओ के अलावा, आरबीआई को शायद उम्मीद है कि अल्पावधि प्रतिफल कम बनाए रखने में अतिरिक्त नकदी मददगार हो सकती है। ज्यादा अधिशेष नकदी संभवत: आरबीआई द्वारा किसी ओएमओ खरीदारी को रोकेगी और यदि आरबीआई दीर्घावधि प्रतिफल में तेजी को सीमित रखना चाहता है तो विशेष ओएमओ को बढ़ावा मिल सकता है।'

न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के बाद सतर्कता बढ़ा रही ओयो

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 3 जनवरी

ओयो ने शुक्रवार को न्यूयार्क टाइम्स (एनवाईटी) की उस खबर की प्रतिक्रिया में कहा कि वह कंपनी को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। एनवाईटी में प्रकाशित खबर में कंपनी की व्यावसायिक प्रणालियां संदिग्ध होने का आरोप लगाया गया था। ओयो के एक अधिकारी ने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कि हमारे मूल्यों को दुनियाभर में मौजूद हजारों कर्मचारियों द्वारा सराहा जाए, और हम अपनी आचार संहिता का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित तौर पर बाहरी ऑडिट कराते हैं। भारत में संपत्ति मालिकों के एक छोटे वर्ग (जिनका भुगतान विवादित है) की शिकायतों के संबंध में समाधान की कोशिश की जा रही है।'

एक दर्जन से अधिक मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के साथ बातचीत के आधार पर एनवाईटी की खबर में आरोप लगाया गया था कि ओयो प्लेटफॉर्म पर शामिल हजारों कमरे गैर-लाइसेंस वाले होटलों और गेस्ट हाउसों से थे, और ओयो ने होटलों से अतिरिक्त शुल्क वसूला तथा होटलों को उनका पूरा पैसा देने से इनकार कर दिया था।

अधिकारी ने कहा, 'हम प्रौद्योगिकी और मजबूत भागीदार सहायता टीमों में भी निवेश कर रहे हैं, जिससे कि सुलह और आपसी तालमेल सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। हमें भरोसा है कि सभी होटल मालिक मेहमानों के लिए श्रेष्ठ अनुभव मुहैया कराएंगे। हम अपने अनुबंधों में उन प्रावधानों का इस्तेमाल बरकरार रखेंगे जिनसे हमें उन हजारों मालिकों की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करने में मदद मिलती हो, जो मेहमानों के लिए लगातार उच्च गुणवत्ता वाला अनुभव प्रदान करते हैं।'

आरओसी की याचिका पर सुनवाई पूरी

अनूप रॉय
मुंबई, 3 जनवरी

बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी गुरुवार को 4 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई। शुक्रवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिलती है। सरकार ने 2003 में जारी किए गए अपने 61,000 करोड़ रुपये के बॉन्डों को भुनाया है।

सरकार सोमवार को नकदी प्रबंधन बिल के जरिये 30,000 करोड़ रुपये की 70 दिन की पूंजी जुटाएगी। आरबीआई ने 4.15 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी खपाने के लिए शुक्रवार को 15,000 करोड़ रुपये की 63-दिन की रिवर्स रीपो नीलामी की।

दिसंबर में व्यवस्था में नकदी 2-2.5 लाख करोड़ रुपये के आसपास थी और 1 जनवरी को यह 3 लाख करोड़ रुपये पर थी। नकदी को लेकर पिछली बार इस तरह की स्थिति 2016 के अंत में नोटबंदी के बाद और 2017 के शुरू में दर्ज की गई थी।

हालांकि नोटबंदी के समय के विपरीत,इस बार केंद्रीय बैंक अतिरिक्त नकदी को खपाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नोटबंदी के दौरान, केंद्रीय बैंक के पास सिर्फ लगभग 7 लाख करोड़ रुपये की बॉन्ड पूंजी थी। हाल के समय में केंद्रीय बैंक ने अपनी बॉन्ड खरीदारी को मजबूत बनाया है। आरबीआई को बैंकों से ली गई रकम के बदले बॉन्ड देने होते हैं।

लेकिन बॉन्ड डीलरों को कुछ मामूली चिंताओं को छोड़कर ज्यादा नकदी अधिशेष से व्यवस्था पर दबाव पड़ने की आशंका नहीं दिख रही है। बदरीश कुल्हाली ने कहा, 'मौजूदा मामले में, ऐसा नहीं लग रहा है कि अतिरिक्त नकदी की वजह से मुद्रास्फीति में तेजी आएगी। अर्थव्यवस्था में मांग अभी भी काफी कमजोर है। अतिरिक्त नकदी से दरें रीपों दरों पर या इससे कुछ नीचे बनी रहेंगी।'

यदि व्यवस्था में लंबे समय तक पर्याप्त नकदी बनी रहे तो क्या हो सकता है? इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के सहायक निदेशक सौम्यजीत नियोगी ने कहा, 'पर्याप्त नकदी पिछले एक साल में व्यवस्थागत जोखिम के समायोजन में मददगार रही है।' नियोगी ने कहा, 'समस्या ऋण के लिए कमजोर मांग की वजह से है। व्यवस्था सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में केंद्रीय बैंक पर अधिक निर्भर हो रही है।'

किया ने 35,000 रुपये तक बढ़ाए सेल्टोस के दाम

किया मोटर्स ने अपनी एसयूवी सेल्टोस के दाम 1 जनवरी से बढ़ा दिए हैं। सेल्टोस के सभी संस्करणों की कीमत में 35,000 रुपये तक की वृद्धि की गई है। किया मोटर्स ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि सेल्टोस के विभिन्न संस्करणों के दामों में 25,000 से 35,000 रुपये के बीच वृद्धि की गई है। दक्षिण कोरियाई वाहन विनिर्माता कंपनी ने पिछले साल अगस्त में भारत में अपना पहला वाहन सेल्टोस पेश किया था। इसकी शुरुआती कीमत 9.69 लाख रुपये रखी गई थी। फिलहाल सेल्टोस की कीमत 9.89 लाख से 16.29 लाख रुपये के बीच है। मारुति सुजूकी, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टोयोटा और रेनो ने पिछले महीने इस बात की घोषणा की थी कि वे जनवरी से वाहनों के दाम बढ़ाएंगी। भाषा

प्रवर्तक विवाद पर गंगवाल ने बुलाई ईजीएम

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 3 जनवरी

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो के प्रवर्तकों राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के बीच जारी सार्वजनिक संघर्ष नए मोड़ पर आ गया है क्योंकि गंगवाल ने कंपनी की असाधारण आम बैठक बुलाई है। असाधारण आम बैठक 29 जनवरी को होगी, जिसमें गंगवाल की मांग के मुताबिक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव पर मतदान होगा। यह बदलाव उस प्रावधान को समाप्त करने के लिए होगा जो दोनों प्रवर्तकों को एक दूसरे की हिस्सेदारी पर पहले इनकार का अधिकार देता है।

दोनों प्रवर्तकों के पास कंपनी की 75 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसकी मौजूदा कीमत 64,627 करोड़ रुपये है। यह कीमत प्रवर्तकों के शुरुआती निवेश के मुकाबले कई गुना है। पिछले महीने गंगवाल ने बाजार नियामक सेबी को पत्र लिखकर कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस में कमी का आरोप लगाया था। गंगवाल ने आरोप लगाया था कि कंपनी के नियंत्रक हिस्सेदार भाटिया ने इसका इस्तेमाल समूह कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज और इंडिगो के बीच सवालिया निशान वाले संबंधित पक्षकार के लेनदेन के क्रियान्वयन के लिए किया।

हालांकि गंगवाल के लिए किसी प्रस्ताव को पारित कराना मुश्किल होगा क्योंकि किसी बदलाव के लिए 75 फीसदी शेयरधारकों के समर्थन की जरूरत होगी। लॉ फर्म लूथरा ऐंड लूथरा के सीनियर पार्टनर मोहित सराफ ने कहा, राहुल भाटिया के समर्थन के बिना प्रस्ताव पारित कराना गंगवाल के लिए मुश्किल होगा।

आईआरडीएआई ने किया भुगतान अनुपात तय

बहुलांश विदेशी हिस्सेदारी वाले इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए बीमा नियामक ने लाभांश भुगतान अनुपात उनके शुद्ध लाभ के 75 फीसदी तक सीमित कर दिया है। अगर लाभ में असाधारण आय या लाभ जुड़ी हो तो भुगतान के अनुपात का आकलन ऐसे असाधारण लाभ को अलग करके किया जाएगा। बीमा नियामक आईआरडीएआई ने ये बातें कही। इसके अलावा नियामक ने कहा है कि लाभांश की घोषणा वाले वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण सांविधिक अंकेक्षकों की अनिवार्यता से मुक्त रहेगा। *बीएस*

रतन टाटा, वेणु श्रीनिवासन पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय

पृष्ठ-1 का शेष

इसके बाद मिस्त्री परिवार की कंपनी ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई में अपील की थी, लेकिन निर्णय उनके पक्ष में नहीं आया। एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ परिवार की निवेश कंपनियों ने एनसीएलएटी में अपील की थी। एनसीएलएटी ने 18 दिसंबर को टाटा संस को मिस्त्री को बतौर कार्यकारी चेयरमैन बहाल करने का आदेश दिया था। मिस्त्री परिवार की निवेश कंपनियों की टाटा संस में 18.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी टाटा समूह की कंपनियों सहित छोटे निवेशकों के पास है।

टाटा ने कहा कि एनसीएलएटी का आदेश इस बात पर आधारित है कि टाटा संस पर केवल दो समूहों का नियंत्रण है। टाटा ने कहा, 'टाटा और मिस्त्री समूह के बीच कभी भी साझेदारी जैसा कोई संबंध नहीं था। साइरस मिस्त्री को टाटा संस का कार्यकारी निदेशक बनाए जाने का निर्णय पूरी तरह पेशेवर स्तर पर लिया लिया गया था न कि उन्हें एसपी ग्रुप के प्रतिनिधि के तौर पर इस पर पर बहाल किया गया था।' टाटा ने कहा कि मिस्त्री को इस शर्त पर टाटा संस का चेयरमैन बनाया गया था कि वह एस परिवार के कारोबार से स्वयं को अलग करेंगे। टाटा ने कहा, 'मिस्त्री ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे, जिससे समूह के भीतर कई वरिष्ठ लोग अलग-थलग पड़ गए थे।'

अब अस्पतालों की रेटिंग की बारी

नम्रता आचार्य और सुब्रत पांडा
कोलकाता/मुंबई, 3 जनवरी

आधारभूत स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मानकीकरण के बाद भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) बीमा दावों के लिए अस्पतालों की रेटिंग के जरिये स्वास्थ्य सेवाओं के मानकीकरण की योजना बना रहा है। आईआरडीएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नियामक अस्पतालों की रेटिंग के लिए एनएबीएच (अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) से चर्चा कर रहा है।

रेटिंग तंत्र के तहत बीमाकर्ता अस्पताल में डॉक्टरों या उपकरण की संख्या जैसे सुविधाओं पर आधारित ग्रेड के आधार पर बीमा की राशि तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पांच सितारा अस्पताल के मुकाबले तीन सितारा अस्पतालों के लिए बीमा की राशि अलग होगी। रेटिंग तंत्र के सिलसिले में नियामक पहले से ही बीमा कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है।

आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस के मुख्य कार्याधिकारी मयंक बथवाल ने कहा, 'फिलहाल अस्पताल के वातावरण पर बीमाकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। रेटिंग से काफी हद तक अस्पताल की सेवाओं के संकेत मिल जाएंगे। यह विचार अब भी चर्चा के स्तर पर है और रेटिंग किन मानदंडों पर आधारित होगा यह फिलहाल देखना बाकी है।'

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अंडरराइटिंग, क्लेम्स, रीइंश्योरेंस ऐंड एक्चुअरी के प्रमुख संजय दत्ता ने कहा, 'अस्पतालों की रेटिंग पर हमने नियामक के साथ चर्चा की है। यह कदम इस क्षेत्र के लिए काफी लाभप्रद होगा।'

आईआरडीएआई के पास पहले से ही स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स (टीपीए) नेटवर्क में अस्पतालों और चिकित्सा दैनिक देखभाल केंद्रों की पंजी है। इसे रोहिणी (रजिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल्स इन नेटवर्क ऑफ इंश्योरर्स) कहा जाता है। इस डेटाबेस में करीब 33,000 विशिष्ट अस्पताल और चिकित्सा दैनिक देखभाल केंद्र दर्ज हैं।

उल्लेखनीय है कि आईआरडीएआई पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मानकीकरण के लिए काम कर रहा है ताकि आम आदमी तक इसकी बेहतर पहुंच हो। पिछले वर्ष सितंबर में यह स्वास्थ्य बीमा ठेकों में बहिष्करण के मानकीकरण पर दिशानिर्देश लेकर आया था।

गुरुवार को इसने मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर दिशानिर्देश जारी किए जिसमें सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की बीमित राशि और न्यूनतम 1 लाख रुपये तक की बीमित राशि वाले उपभोक्ताओं के लिए उनके आधारभूत स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम उत्पाद पेश करने के लिए कहा गया है।

मानक उत्पाद में आधारभूत अनिवार्य कवर होने चाहिए। मानक उत्पाद के साथ कोई अतिरिक्त या वैकल्पिक कवर पेश करने की अनुमति नहीं होगी और बीमाकर्ता आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों को पूरा करने वाले प्रस्तावित कवर की पेशकश को ध्यान में रखकर बीमा की कीमत तय कर सकते हैं। पॉलिसीबाजारडॉटकॉम पर हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस हेड अमित छाबड़िया ने कहा, 'इसके बाद स्वास्थ्य बीमा बाजार काफी व्यापक होगा। इस उत्पाद के साथ स्वास्थ्य बीमा को लेकर काफी जागरूकता आएगी।' वित्त वर्ष 2020 के दौरान सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के तौर पर 44,873 करोड़ रुपये जुटाए। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 21 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

उत्पादों के मानकीकरण के बाद नियामक की तैयारी

- अस्पतालों की रेटिंग के लिए नियामक की एनएबीएच से चल रही है चर्चा
- नियामक पहले से ही बीमा कंपनियों के साथ कर रहा बात
- बीमाकर्ता अस्पताल में डॉक्टरों या उपकरण की संख्या जैसी सुविधाओं पर आधारित ग्रेड के आधार पर बीमा की राशि तय कर सकते हैं

स्टार हेल्थ ऐंड एलाइड इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक आनंद रॉय ने कहा, 'फिलहाल बाजार में बहुत सारे उत्पाद हैं जिससे ग्राहकों के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब एक आधारभूत उत्पाद होने से स्वास्थ्य बीमा के दायरे में विस्तार होगा।'

उन्होंने कहा कि हमने बीमाकर्ता के साथ अस्पतालों की रेटिंग के मसले पर चर्चा की है। स्वास्थ्य बीमा का क्षेत्र सालाना 20 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। पिछले वर्ष 2 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य पॉलिसी जारी किए गए जिसमें करीब 47.2 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है।

मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस की मुख्य परिचालन अधिकारी प्रिया गिलबिले ने कहा, 'इस कदम से स्वास्थ्य बीमा का दायरा काफी बढ़ेगा और इससे और अधिक स्वचालन भी आएगा। अस्पतालों की रेटिंग इस उद्योग के लिए काफी सकारात्मक कदम साबित होगा।'

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी राकेश जैन ने कहा, 'अंततः हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा को लेकर जागरूकता बढ़े। मानकीकरण के विचार से काफी लोगों को उत्पाद के बारे में सहमत करने में मदद मिलती है। यह एक प्रकार का वित्तीय समावेशन है। मुख्य ध्येय स्वास्थ्य बीमा में लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। जब बहुत अधिक विविधता होती है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। और जाहिर तौर पर जब स्वास्थ्य प्राथमिक विषय नहीं हो तो लोगों को इसे खरीदने के लिए मनाने को लेकर आसान दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। यह एक अच्छी शुरुआत है और यह देश में स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानक भी तैयार करेगा। तब जाकर बीमाकर्ता अभिनव प्रयोग करेंगे और बेहतर उत्पादों के साथ सामने आएंगे। लिहाजा इसके दोहरे लाभ हैं।'

बड़े व मझोले क्षेत्र की ऋण गुणवत्ता में आई कमी

अभिजित लेले
मुंबई, 3 जनवरी

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान बड़े व मझोले उद्यम (एलएमई) क्षेत्र की ऋण गुणवत्ता गिरकर 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। छोटे आकार की इकाइयों (एसएमई) की संपत्ति की गुणवत्ता भी कम हुई है, लेकिन इसमें मामूली गिरावट आई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने यह जानकारी दी है। एलएमई क्षेत्र में संशोधित क्रेडिट रेश्यो वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 9 महीनों के दौरान गिरकर 0.92 रह गया। जिन इकाइयों की वित्तीय स्थिति की इस अवधि के दौरान समीक्षा की गई है, उनमें 70 प्रतिशत इकाइयां एलएमई हैं। इस तरह से इसका बड़ा हिस्सा होने के कारण कुल मिलाकर साख की गुणवत्ता कम हुई है।

संशोधित क्रेडिट रेश्यो (एमसीआर) को उन्नयन और पुनःपुष्टि और अवनति एवं पुनःपुष्टि के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। एसएमई क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में भी गिरावट आई है, लेकिन कुल मिलाकर ऋण की गुणवत्ता इस क्षेत्र में स्थिर नजर आई। इस क्षेत्र का एमसीआर अप्रैल-दिसंबर 2019 अवधि के दौरान 1 से ऊपर रहा। अप्रैल दिसंबर 2019 के दौरान एमसीआर घटकर 1.07 रह गया, जो अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान 1.12 था। केयर ने कहा कि विनिर्माण, सेवा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की इकाइयों की अवनति की मुख्य वजह पूंजीगत ढांचे में गिरावट होना है।

निर्यातकों को एमईआईएस लाभ अब 31 मार्च तक

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 3 जनवरी

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) ने आज साफ किया कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के तहत निर्यातकों को मिलने वाला लाभ 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने आधिकारिक रूप से इस विस्तार की घोषणा नहीं की है। फियो ने कहा कि यह योजना 1 अप्रैल से लागू होने जा रही नई अद्यतन विदेश व्यापार नीति तक जारी रहेगी।

सरकार ने अपनी सबसे बड़ी निर्यात संवर्धन योजना बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने इसे कारोबार बिगाड़ने वाली योजना के रूप में वर्गीकृत किया है। इसकी जगर पर सीधी सब्सिडी मुहैया कराने की योजना बनाई गई है, जिसकी अनुमति है। अमेरिका के साथ अहम कारोबारी विवाद में भारत के खिलाफ नवंबर 2019 में नियम आया, जिसमें आदेश दिया गया था कि सभी निर्यात संवर्धन योजनाएं अगले 4 महीनों में रोकी जानी चाहिए।

सितंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वस्तुओं के निर्यात के लिए रेमिशन आफ ड्यूटीज ऑर टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (आरओडीटीईपी) नाम की नई योजना की घोषणा की थी, जो एमईआईएस की जगह लेगा। अधिकारियों ने कहा कि नई आरओडीटीईपी योजना बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, हालांकि दरों पर फैसला होना अभी बाकी है।

लेकिन घरेलू उद्योग ने इसे वापस लेने का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि कारोबार में वैश्विक मंदी और अमेरिका व चीन के बीच कारोबारी जंग को देखते हुए सरकार के समर्थन की जरूरत है।

फियो के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने कहा, 'परिधान और मेड-अप्स के विशेष उत्पादों को एमईआईएल लाफ देने के मसले का जल्द ही समाधान होने की संभावना है ।'

11 राज्यों में खुदरा महंगाई 6 प्रतिशत पार

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 3 जनवरी

देश के 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में से करीब 30 प्रतिशत में खुदरा महंगाई दर नवंबर में 6 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई। मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी की वजह से ऐसा हुआ है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर की इस श्रेणी में आने वाले 11 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं।

नवंबर महीने में जहां ओडिशा में अक्टूबर की तुलना में महंगाई दर तेजी से बढ़ी है, वहीं अन्य राज्यों में भी हाल के महीनों में तेजी आई है। ओडिशा में नवंबर में महंगाई दर बढ़कर 7.23 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि इसके पहले के महीने में यह 3.35 प्रतिशत थी। एक महीने में महंगाई करीब 4 प्रतिशत बढ़ी है। ऐसा इसलिए हुआ कि ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर नवंबर में 7.37 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो एक महीने पहले 2.61 प्रतिशत थी। इसमें 4.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं शहरी इलाकों में राज्य में महंगाई अक्टूबर के 5.32 प्रतिशत से 1.54 प्रतिशत अंक बढ़कर नवंबर में 6.86 प्रतिशत हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि बेवरिज के साथ खाद्य महंगाई दर में नवंबर में दो अंको की बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर के महज 4.23 प्रतिशत से बढ़कर यह अगले महीने 10.65 प्रतिशत पर पहुंच गई।

दरअसल ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में भी खाद्य एवं बेवरिज की महंगाई दर करीब दो अंकों में बढ़ी है। अक्टूबर के 2.89 प्रतिशत के मामूली स्तर ये यह नवंबर में बढ़कर 9.97 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो एक महीने में 7 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई दर नवंबर में 13.09 प्रतिशत पर रही, जो इसके पहले महीने में 9.69 प्रतिशत पर थी।

ओडिशा में महंगाई दर में तेज बढ़ोतरी को इस रूप में देखा जा सकता है कि कैलेंडर साल 2019 के जनवरी महीने में राज्य में कोई महंगाई नहीं थी। दरअसल सितंबर में कुछ सुधार हुआ, जबकि शेष महीनों में यह शून्य से 2.21 प्रतिशत के बीच थी। बहरहाल ओडिशा में महंगाई दर लक्षद्वीप, त्रिपुरा और मणिपुर की तुलना में कम रही। लक्षद्वीप में नवंबर में महंगाई दर 10.25 प्रतिशत रही, जो इसके पहले महीने में 7.76 प्रतिशत थी। इस राज्य में महंगाई मई में ही 6 प्रतिशत पार कर गई थी। यह एकमात्र राज्य है, जहां नवंबर में महंगाई दर दो अंकों में पहुंच गई।

त्रिपुरा में भी महंगाई दर जुलाई में 6 प्रतिशत पार कर गई। मणिपुर में नवंबर में महंगाई दर कम होकर 7.9 प्रतिशत पर आई, जो इसके पहले महीने में 8.01 प्रतिशत थी।

ज्यादातर राज्यों में खाद्य वस्तुएं महंगी होने का असर महंगाई दर पर पड़ा है। यहां तक कि मणिपुर में महंगाई दर में गिरावट कुल मिलाकर कीमतों में कमी की वजह से हुई। बहरहाल गिरावट के बावजूद राज्य में खाद्य महंगाई नवंबर में 10.96 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रही। राष्ट्रीय औसत के हिसाब से खाद्य महंगाई दो अंकों को छूते हुए नवंबर में 10.01 प्रतिशत पर पहुंच गई और ऐसा चालू कैलेंडर वर्ष में पहली बार हुआ। ऐसा सब्जियों, खासकर प्याज के दाम में तेजी की वजह से हुआ। इसके पहले महीने में यह 7.89 प्रतिशत पर थी।

पाकिस्तान को यूएई से मिली 20 करोड़ डॉलर की मदद

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पाकिस्तान में छोटे एवं मझोले उद्यमों के विकास के लिए 20 करोड़ डॉलर की सहायता दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के वित्त सलाहकार ने यह जानकारी दी। अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के पाकिस्तान दौर के एक दिन बाद यह घोषणा की गई। प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार अब्दुल हफीज शेख ने गुरुवार को कहा, 'इस पूंजी का उपयोग छोटे व्यवसायों को बढ़ाने और रोजगार सृजन में किया जाएगा।' *भाषा*

विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 2.520 अरब डॉलर बढ़कर 457.468 अरब डॉलर केरिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। आरबीआई के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 45.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 454.948 अरब डॉलर पर था। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में वृद्धि की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी आई है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 2.203 अरब डॉलर बढ़कर 424.936 अरब डॉलर पर पहुंच गई। स्वर्ण भंडार भी 26 करोड़ डॉलर बढ़कर 27.392 अरब डॉलर हो गया। *भाषा*

बीएस सूडोकू 3630

	4		5			7		3
			4		9	6		
		2		7				
2				9				6
		1	8		7	9		
8				2				4
				8		4		
		8	2		3			
6		4			1		3	

परिणाम संख्या 3629

5	4	8	9	6	3	1	2	7
9	1	7	2	4	5	6	8	3
2	3	6	8	7	1	4	9	5
1	6	2	7	8	9	3	5	4
7	8	3	1	5	4	9	6	2
4	9	5	3	2	6	8	7	1
3	7	1	6	9	2	5	4	8
6	2	4	5	1	8	7	3	9
8	5	9	4	3	7	2	1	6

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★★

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2205/2210, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4650/4700, तिल सफेद 9600/9800, सोया (टीन) 1575/1625, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1600/1700,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2210/2220, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1443, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1522, फ्लैक 1462, डीएमओ 1051, टरपीन लेस बोल्ड 1548

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1230/1265, खुरपा 1100/1160,चाकू 1050/1200, रसकट 980/1000, शक्कर 1200/1250, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3340, सिहोरा 3210, बुंदकी 3250, बुढ़ाना 3315,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1200/1250, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4650, खल: सरसों 2300/2400, बिनौला 2550/2700, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2240/2250, मक्की 2250/2275, बाजरा 1940/1945, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3900/3950, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4780/4800,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2100/2125, ग्वार 3900/3950, जौ 2190/2200,

जोधपुर
गेहूं 2100/2150, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4150/4200, ग्वारगम 7700/7800, बाजरा (गुजरात) 1990/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4350/4450, काबली चना 5100/6000, मूंग 6300/6500,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)132, राइसब्रान (अखाद्य) 127, खल सरसों 2100, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल 1300, कंटीन्यूअस 1325,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7650/8600, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8800/9500, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6100/6200, सेला 5600/5700, शरबती साधारण सेला 3800/3900, शरबती स्टीम 4100/4200,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4040/4070, हरियाणा 4020/4040, राजस्थान 3980/4040, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2600/2700, सरसों खल 2250/2260,

फाजिल्का
गेहूं 2265/2275, सरसों 4700/4800 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4050/4100, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5200/5400, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2700/2750,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2280/2290, चावल परमल कच्चा 2500/2550, से ला 2400/2425, मक्की यूपी 2375/2400, बिहार 2500/2525, दाल उड़द छिलका 9500/10900, चना देशी 5200/5300, दाल चना 5500/5700, काबली चना 5300/6200, राजमां चित्रा पुणे 7200/8600, चीन 7900/8500,

करनाल
गेहूं दड़ा 2230/2240, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, स्टीम 6100/6200,

हिसार
ग्वार 3850/3900, जौ 1775/1780, सरसों 4350/4400, मूंग 6500/6700, गेहूं 2170/2180,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1080/1090, मैदा 1190/1200, देशी घी (एक ली/जार) 390/495, रिफाइंड (टीन) 1590/1600,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4350/4400, खल बिनौला मोटी 2400/2500, बिनौला 2800/3400, सरसों तेल 9600/9650, गेहूं 2200/2225, ग्वार 3950/4000, बाजरा 1950/2000 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 274

एशिया के सवाल

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

जब गुन्नार मिर्डल 1960 के दशक के आखिर में अपनी किताब 'एशियन ड्रामा' लिख रहे थे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बांग्लादेश 50 साल बाद आर्थिक मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले देश के तौर पर सामने आएगा। उस समय तक बांग्लादेश का वजूद भी नहीं था। हेनरी किसिंजर ने जिस देश को एक अंतरराष्ट्रीय बास्केट बताते हुए नकार दिया था, उसने अब मानव विकास सूचकांकों और आर्थिक वृद्धि दरों के मामले में दक्षिण एशियाई देशों को पीछे छोड़ दिया है। उसकी प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान की 1,388 डॉलर प्रति व्यक्ति आय के बरक्स 1,905 डॉलर है और अब वह भारत की 2,171 डॉलर प्रति व्यक्ति आय से भी बहुत पीछे नहीं है।

करीब 2,300 पृष्ठों की इस किताब को अक्सर महान कृति बताया जाता है। लेकिन वह भी कई जगह गलती कर गए। मसलन, क्या चीन और भारत के लिए जनसंख्या एक भारी बोझ साबित होगी लेकिन शुरुआती हालात के मामले में वह सही भी साबित हुए। एशियन ड्रामा की 50वीं सालगिरह पर दीपक नैयर ने अपनी नई किताब 'रिसर्जेंट एशिया: डाइवर्सिटी इन डेवलपमेंट' में एशिया को नई नजर से देखने की कोशिश की है।

नैयर की किताब एशियाई देशों में अपनाए गए अलग विकास पथों का जिक्र करती है जो अक्सर बंद बाजार खोलने में उपनिवेशवादी भूमिका की उपज रही है। शशि थरूर ने अपनी किताब 'ऐन एरा ऑफ डार्कनेस' में इस संभावना को परखा है कि अगर भारत उपनिवेश नहीं बनता और वहां रेलवे एवं आधुनिक प्रशासन नहीं आते तो क्या वह अपना मुकाम हासिल कर लेता? लेकिन यह एकदम सच है कि बाहरी प्रभाव के बगैर कई देशों में भूमि सुधार लागू ही नहीं हुए रहते। इसी तरह निर्यात को अपनी मजबूती बनाने वाले ताइवान और दक्षिण कोरिया क्या अपने घरेलू बाजार बहुत छोटे होने का अहसास होने के बाद आयात प्रतिस्थापन को लेकर प्रयोग करते?

'एशियाई चमत्कार' में सफलता का श्रेय निरंकुश शासकों को किस हद तक जाता है? वे शासक आज के एर्दोगन से किस तरह अलग थे जिनकी आंखों के सामने तुर्की की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है? तेल, सोना और कोयला निर्यात के दम पर जिंदा रूस के व्लादीमिर पुतिन जैसे निरंकुश नेता हैं वहीं ब्राजील अपनी औसत वृद्धि दर को छिपाने की कोशिश कर रहा है? एशिया के पुराने नेता अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक पहुंचाने की समझ के मामले में हमारे अपने नरेंद्र मोदी से किस तरह अलग थे?

लोकतंत्र बनाम निरंकुशता की बहस में न पड़ते हुए इतना कहा जा सकता है कि लोकतंत्र स्वयं में एक साध्य है और यह नियंत्रण एवं संतुलन के अधिक अनुकूल है। नैयर मानते हैं कि आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक लोकतंत्र न तो आवश्यक है और न ही पर्याप्त है। उनका सुझाव है कि वेबर अवधारणा वाली नौकरशाही एशिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की सफलता के लिए अधिक जिम्मेदार थीं। एशिया में साम्यवादी से लेकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की मौजूदगी और विभिन्न देशों में एक ही तरीके के अलग परिणाम आने संबंधी मिर्डल के आकलन को देखते हुए क्या भारत को प्रशासनिक इंतजामों में अधिक प्रयोग करने का इरादा दिखाना चाहिए?

क्या यह सदी एशिया की होगी? नैयर ऐसा नहीं मानते हैं जिसका कारण शायद यह है कि एशिया के केवल दो-तीन देश ही उच्च आय स्तर तक पहुंच पाए हैं। लेकिन ब्रिक्स के प्रिज्म से देखें तो शक्ति संतुलन में बदलाव एक पूर्व-निश्चित निष्कर्ष दिखता है। ब्रिक्स समूह के चार देशों को वर्ष 2025 तक छह शीर्ष पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी का आधा होना था लेकिन वे इसे पहले ही पार कर चुके हैं। इसका कारण एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का अच्छा प्रदर्शन है लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिद्वंद्विता उन्हें साझा मकसद के लिए साथ मिलकर काम करने से रोकेगी।

एशियन ड्रामा लिखे जाने के आधी सदी बाद हालत यह है कि भारत एक से अधिक बार मौके गंवा चुका है। अगर अब हम एक या दो लेवियाथन के दबदबे वाली हॉब्सवादी दुनिया में नहीं घसीटे जाना चाहते हैं तो भारत को यह तय करने की जरूरत है कि वह नियम बनाने वाले या नियमों पर चलने वाले में से क्या बनना चाहता है? क्या हमारे पास चीन की सामरिक चुनौती का कोई जवाब है? अगर नहीं तो फिर हमारे पास क्या विकल्प हैं? एशिया के 50 वर्षों के इतिहास से निकले ऐसे तमाम सवालों के जवाब सदी के तीसरे दशक के आरंभ में फौरन तलाशने की जरूरत है।

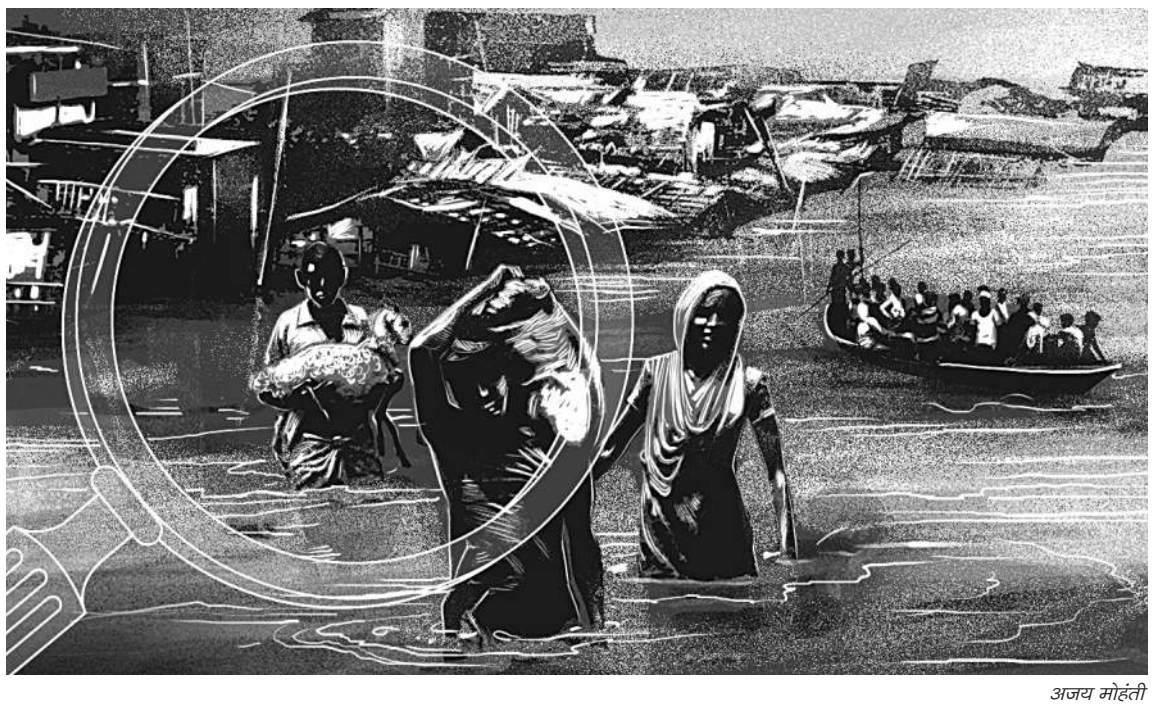

अजय मोहंती

प्राकृतिक आपदा के बाद गरीबों की हालत

सीएमआईई के आंकड़ों ने आपदाओं के बारे में पहले से चली आ रही अवधारणा को तोड़ा है। बता रहे हैं **अजय शाह**

हाल में किए गए एक शोध में चेन्नई में वर्ष 2015 में आई विनाशकारी बाढ़ के बारे में नए तथ्य सामने आए हैं। दिलचस्प बात है कि घरेलू आय में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन बाढ़ आने के बाद एक साल तक घरेलू खर्च में काफी तेजी आई। स्वास्थ्य और ईंधन/बिजली पर खर्च बहुत बढ़ा। इस अवधि के बाद लोगों ने इस स्थिति को बदल दिया और कम खर्च करना शुरू कर दिया। संभवत: वे अपने बहीखाते को दुरुस्त करने में लगे थे। गरीबों के लिए खर्च में तेजी कम थी जबकि संभवत: बाढ़ के कारण वे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। शायद उधारी तक पहुंच बढ़ने से उन्हें मदद मिली होगी।

किसी भी राष्ट्र के जीवन में प्राकृतिक आपदाएं अहम घटनाएं होती हैं। हममें से अधिकांश लोग अपने जीवनकाल में एक या उससे अधिक बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से रूबरू होते हैं। यह पता लगाने के लिए ज्यादा शोध की जरूरत है कि किसी प्राकृतिक आपदा के बाद स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक रूप से शोधकर्ता आपदा प्रभावित इलाके में डेरा डालते हैं और वहां की परिस्थितियों का आकलन करते हैं। लेकिन इसकी दो सीमाएं हैं। हमने आपदा से पहले ही परिस्थितियों का आकलन नहीं किया है और साथ ही हम अप्रभावित इलाकों की परिस्थितियों का आकलन नहीं कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जा सकता है।

सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे (सीपीएचएस) से आकलन की नई संभावनाएं सामने आई हैं। इसमें हर चार महीने में 170,000 घरों का आकलन किया जाता है। मान लीजिए कि कोई आपदा दो सर्वेक्षणों के बीच आती है, तो हमें चार महीने की अवधि मिल जाएगी जिसमें एक ही परिवार की आपदा से पहले और बाद की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। यह आकलन पूरे देश में किया जाता है, इसलिए नियंत्रणों की पहचान करना संभव है।

हाल में एक शोध पत्र में इला पटनायक, रेणुका साने और मैंने 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ का अध्ययन किया। परिवारों पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए हमने परीक्षण के तौर पर इस नई दृष्टिकोण को अपनाया।

पहला सवाल आय के बारे में है। पहली नजर में हमें लग सकता है कि कई बाढ़ के कारण कई कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ होगा, रेहड़ी पटरी वालों का काम धंधा बंद हो गया होगा और उनकी आय कम हो गई होगी। लेकिन हमें इसमें गहरे जाने की जरूरत है। बाढ़ का पानी घरों में घुसने के कारण लोग घरों में खाना नहीं पका पाए जिससे खाना बेचने वालों की बिक्री बढ़ गई। बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोगों ने अपने घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। सरकार ने राहत एवं पुनर्निर्माण पर बहुत पैसा खर्च किया। हर व्यक्ति को इसके लिए 2,000 रुपये दिए गए। बढ़े खर्च ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ा दिया जिसने बाढ़ के प्रभाव को खत्म कर दिया। इसके परिणामस्वरूप परिवारों की कुल आय में कोई बदलाव नहीं हुआ।

दूसरा सवाल खर्च को लेकर है। परंपरागत अवधारणा यह है कि प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति बदतर हो जाती है और वे कम खर्च करते हैं। लेकिन चेन्नई बाढ़ के आंकड़ों में ऐसा नहीं हुआ है। बाढ़ के दौरान और इसके तुरंत बाद खर्च में 32 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। लोग खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य और ईंधन/बिजली पर ज्यादा खर्च कर रहे थे। करीब 10 महीने में खर्च फिर से सामान्य स्थिति में पहुंच गया और उसके बाद वास्तव में यह बाढ़ पूर्व की स्थिति से भी कम हो गया। इसकी वजह यह थी कि लोग फिर से अपने बहीखाते को दुरुस्त करने लगे थे। बाढ़ के दौरान समृद्ध परिवारों को जानमाल का कम से कम नुकसान हुआ होगा। मकान की ऊपरी मंजिलें बाढ़ से प्रभावित नहीं हुईं और उनका बीमारी से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा। नकदी और उधारी तक उनकी पहुंच बरकरार रही होगी। इसलिए हम देख सकते हैं कि ऐसे परिवारों के खर्च में थोड़े समय के लिए तेजी आई और उसके बाद सामान्य स्थिति बहाल हो गई।

मकान और परिसंपत्तियों के बरबाद होने और स्वास्थ्य पर पड़े प्रभाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि गरीबों पर बाढ़ की ज्यादा मार पड़ी। आदर्श स्थिति में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए खपत में बहुत तेजी की जरूरत है। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक गरीबों के लिए खपत में थोड़ा बहुत तेजी आई। यह गरीबों के लिए वित्तीय बाधाओं और मुसीबतों को दर्शाता है।

वित्तीय आपदा से निपटने के लिए वित्त की अहम भूमिका होती है। लेकिन चेन्नई के आंकड़ों से पहले एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। कुछ ही परिवारों ने बाढ़ के बाद उधार लिया, बचत की या परिसंपत्तियां खरीदी। इससे यह चिंता भी पैदा होती है कि क्या भारतीय वित्तीय व्यवस्था उस स्थिति में अपना काम करने में सक्षम है जब लोगों को वित्त की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नीतिगत बाधाओं का पता लगाना और उनकी पहचान करना जरूरी है जो मुनाफा कमाने वाली वित्तीय कंपनियों को चेन्नई जैसे आपदा प्रभावित स्थानों में उधारी बढ़ाने से रोकती हैं। ये दुश्वारियां एक बीमार वित्त व्यवस्था की व्यापक तस्वीर के अनुकूल हैं।

चेन्नई में बाढ़ वहां के बाशिंदों के लिए बहुत भयावह अनुभव रही लेकिन अवधारणा के स्तर पर बाढ़ के बाद का प्रदर्शन उतना अच्छा रहा जितना भारत में रह सकता है। तमिलनाडु की राज्य क्षमता बहुत अधिक है और चेन्नई देश के सबसे अमीर स्थानों में से एक है। मीडिया ने पूरी शिद्दत के साथ बाढ़ का प्रचार-प्रसार किया जिससे सरकार तुरंत हरकत में आई और राहत एवं पुनर्निर्माण का काम आननफानन में हुआ। देश के दूसरे स्थानों पर राज्य की सीमित क्षमता, प्रभावित लोगों का रुतबा, वित्तीय कंपनियों की कम मौजूदगी और मीडिया की बेरुखी के कारण शायद इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती। चेन्नई के आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि यह भारत में प्राकृतिक आपदा के बाद राहत एवं पुनर्निर्माण का सबसे बेहतर प्रदर्शन है।

इस काम की अहमियत इतने तक ही सीमित नहीं है कि चेन्नई में 2015 में आई बाढ़ के बाद क्या हुआ। यहां आकलन के लिए जो रणनीति विकसित की गई, वह सामान्य है और केवल चेन्नई बाढ़ के बारे में ही नहीं है। कई शोधकर्ता इन तरीकों का इस्तेमाल कर इसी तरह के अध्ययन करेंगे जिससे एक नई समझ पैदा हो सकती है कि देश में प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं के बीच सीधी तुलना की भी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि दो आपदाएं एक तरह की नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए केरल की बाढ़ की तुलना चेन्नई की बाढ़ से नहीं की जा सकती है।

(लेखक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।)

नववर्ष 2020 में मीडिया उद्योग के लिए कामना

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

देश में अनिश्चितता और आशंका का माहौल है। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है और उसका सामाजिक तानाबाना बिखर रहा है। और ऐसा लगता है कि जिन लोगों पर इसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, वे कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं।

देश के 1,67,400 करोड़ रुपये के मीडिया और मनोरंजन उद्योग का भी यही हाल है। मैं लंबे समय से इस उद्योग से जुड़ी हूं और नए वर्ष में मेरी पहली और सबसे बड़ी कामना स्थिर विनियामक माहौल की है। ऐसा माहौल जो उद्योग की प्रगति की राह सुगम बनाए।

उदाहरण के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए शुल्क आदेश यानी एनटीओ को लीजिए जिसे पिछले साल फरवरी में लागू किया गया था। इससे उद्योग में पारदर्शिता और व्यवस्था कायम हुई। यह ऐसा उद्योग है जहां जमीन पर 43,500 करोड़ रुपये की उगाही होती है लेकिन इसमें से 60-70 फीसदी राशि हमेशा वापस नहीं आती है। मगर इससे कई तरह की समस्याएं भी पैदा हुई हैं। मसलन कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, जटिल पैकेजों की शिकायतें आ रही हैं, सैंपलिंग में कमी आई है, केबल से डीटीएच या टीवी से ऑनलाइन विकल्पों का चलन बढ़ा है। इनमें से किसी से भी ट्राई के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होती है। ट्राई का सबसे बड़ा लक्ष्य दर्शकों को अपनी पसंद के चैनल देखने का विकल्प देना था। अगस्त में प्राधिकरण ने शुल्क पर एक और मसौदा पत्र जारी किया। अब कुछ और सिफारिशों के बारे में बात चल रही है।

2004 में ट्राई को प्रसारण क्षेत्र का नियामक बनाया गया था। तबसे वह शुल्क में संशोधन से जुड़े 35 आदेश जारी कर चुका है। साथ ही उसने इंटरकनेक्शन और सेवा की गुणवत्ता आदि पर सैकड़ों आदेश दिए हैं। सैटेलाइट ऐंड केबल टीवी मैगजीन के संपादक और पब्लिशर दिनयार कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, 'पिछले 5-10 साल से करीब-करीब हर महीने कोई नया नियम या निर्देश जारी होता है। इससे नियामक की भूमिका दखल देने वाली की बन जाती है और उद्योग का कामकाज अस्थिर, अनिश्चित और विवादास्पद बन जाता है। ऐसे में उद्योग ट्राई के नियमों में कमियां खोजने लगता है जिससे उनमें संशोधन किया जाता है या नए नियम बनते हैं। इस तरह यह चूहे और बिल्ली का कभी न खत्म होने वाला खेल है।' क्या हम 2020 में चूहे और बिल्ली के इस खेल को खत्म कर सकते हैं?

> अधिकांश ओटीटी का अपना एनालिटिक्स है जो उन पर आने वाले ट्रैफिक और उनके द्वारा बिताए गए समय आदि के बारे में जानकारी देता है। इनकी अन्य ओटीटी के आंकड़ों के साथ तुलना की जा सकती है या नहीं भी की जा सकती है। कॉमस्कोर जो आंकड़े देता है, वे ओटीटी के अपने आंकड़ों के दो से तीन गुना कम होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें क्या शामिल किया गया है और क्या नहीं।

टीवी के कारोबार में धीरे-धीरे पारदर्शिता आने लगी है लेकिन डिजिटल की दुनिया में दूर-दूर तक इसकी मौजूदगी नहीं है। मैं चाहती हूं कि डिजिटल के क्षेत्र में भी पारदर्शिता आए। देश के आधा दर्जन क्वालीफायर को छोड़ दें तो आपके लिए देश में शीर्ष 10 ओटीटी या न्यूज साइट की सूची खोजना संभव नहीं है। टीवी के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल और प्रिंट के लिए रीडरशिप स्टडीज काउंसिल ऑफ इंडिया है। लेकिन डिजिटल के लिए ऐसी कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है जो विज्ञापनदाताओं, मीडिया या कारोबारियों को विश्वसनीय आंकड़े दे सके।

अधिकांश ओटीटी का अपना एनालिटिक्स है जो उन पर आने वाले ट्रैफिक और उनके द्वारा बिताए गए समय आदि के बारे में जानकारी देता है। इनकी अन्य ओटीटी के आंकड़ों के साथ तुलना की जा सकती है या नहीं भी की जा सकती है। कॉमस्कोर जो आंकड़े देता है, वे ओटीटी के अपने आंकड़ों के दो से तीन गुना कम होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें क्या शामिल किया गया है और क्या नहीं। क्या ये अलग-अलग उपकरणों पर लॉगिन और एकल यूजर पर आधारित होते हैं? क्या वे सभी उपकरणों का जोड़ होते हैं जिनमें दोहराव नहीं होता है? क्या साइट या ऐप पर आने वाले केवल विजिटर हैं और उन्होंने वीडियो नहीं देखा है? साथ ही ओटीटी की किसी भी सूची में सदस्यता वाली सेवाएं जैसे नेटफ्लिक्स या एमेजॉन प्राइम वीडियो शामिल नहीं होंगी। चूंकि उन्हें विज्ञापन राजस्व की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उनके आंकड़े सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

क्या डिजिटल कंपनियां साथ मिलकर हमें ऐसी व्यवस्था दे सकती हैं जिससे उनके कारोबार के आंकड़ों का सटीक पता लगाया जा सके?

मेरी तीसरी और शायद सबसे बचकानी कामना यह है कि भारतीय खबरिया चैनल गायब हो जाएं। या कम से कम रातोरात सही मायनों में खबरिया संस्थानों में बदल जाएं। जिन चीजों ने देश में लोकतांत्रिक तानेबाने को नुकसान पहुंचाया है, उनमें टीवी न्यूज की भूमिका सबसे बदतर है।

मेरी सबसे उत्कट कामना यह है कि हम एक ऐसे जागरूक देश बन जाएं कि व्हाट्सऐप पर आने वाले कुछ कूड़े के कारण एकदूसरे के खून के प्यासे न बनें। हम ऐसे देश बनें जहां हम व्यक्तिगत आपेक्षों से बचते हुए तर्कसंगत दलीलें दें। क्या यह अच्छा सपना नहीं है? सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं।

कानाफूसी

भगवान भरोसे एयर इंडिया!

क्या सरकार एयर इंडिया का कारोबार ठप होने से बचाने के लिए किसी दैवीय कृपा की आस लगाए बैठी है? कम से कम एक वरिष्ठ अधिकारी ने पर्दे के पीछे तो यही प्रतिक्रिया दी है। एक संवाददाता ने सवाल किया कि अगर सरकारी विमानन कंपनी को जुलाई तक कोई खरीदार नहीं मिलता तो क्या होगा? क्या इसका अर्थ यह होगा कि एयर इंडिया भी जेट एयरवेज की राह पर चलते हुए परिचालन बंद कर देगी? इसपर अधिकारी ने कहा, 'सब भगवान भरोसे है।' इससे आगे कुछ जानने से पहले ही संवाददाता को उनकी चुप्पी का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसी खबरें हैं कि वित्त मंत्रालय एयर इंडिया को आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार नहीं है और अगर जुलाई तक इसे नहीं बेचा गया तो कंपनी को बंद किया जा सकता है।

राहुल की वापसी!

आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव के तौर पर राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष के रूप में वापसी कर सकते हैं और राहुल तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल बैठा लिया गया है। इस बदलाव से पार्टी में युवा तथा वरिष्ठ नेताओं का मिलाजुला रंग दिखाई देगा। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दोनों समूहों को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई है। इन दिग्गज नेताओं ने हरियाणा में पार्टी को पुनर्जीवित करने में मदद की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की मदद से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखा और झारखंड में चुनावी जीत के लिए पार्टी का नेतृत्व किया। इस सभी प्रयासों ने वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी के सलाहकारों में शामिल करने के लिए प्रेरित किया।

आपका पक्ष

बुलेट ट्रेन के कई लाभकारी पहलू

वर्ष 2022 तक भारत में बुलेट ट्रेन के परिचालन का लक्ष्य रखा गया है। भारत में पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी और इसके लिए पटरी बिछाने का काम शुरू हो चुका है। जापान की तकनीक पर आधारित बुलेट ट्रेन के भारत में दौड़ने के साथ ही भारत भी उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां बुलेट ट्रेन चल रही है। इस जापानी तकनीक की विश्वसनीयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले पांच दशकों में जापान में एक भी दुर्घटना का मामला सामने नहीं आया। अहमदाबाद से मुंबई तक का करीब 8 घंटे का सफर अब करीब ढाई घंटे का रह जाएगा। इससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और लोगों का समय बचेगा। अहमदाबाद और मुंबई के बीच ट्रेन के जो स्टेशन होंगे वहां के लोगों को रोजगार मिलेंगे। इस परियोजना के तहत करीब 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार मिलेंगे। पर्यटन के लिहाज से बुलेट ट्रेन का महत्त्व बढ़ेगा। एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना में जापान का सहयोग 88 हजार करोड़ रुपये का है। हालांकि विरोधियों का तर्क है कि अगर इस धनराशि का प्रयोग कृषि तथा सीमा प्रबंधन में होता तो बेहतर होता। वर्तमान परिदृश्य में बुलेट ट्रेन का विरोध उसके आर्थिक महत्त्व को कम करके आंकना होगा।

मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना में जापान मदद कर रहा है

द्विजेंद्र कौशिक, नई दिल्ली

खेल संस्कृति को बढ़ावा जरूरी

मोदी सरकार ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स टैग लाइन से जो देश के लगभग सभी राज्यों के स्कूलों के विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों में प्रतिभा दिखाने का मौका दिया वह सराहनीय है। सरकार के ऐसे प्रयासों से ही भारत दुनियाभर में हर खेल में अव्वल आ सकता है। भारत में क्रिकेट ही नहीं, बल्कि दूसरे खेलों के खिलाड़ियों और उनकी खेल के प्रति महारत की कमी नहीं है। कमी है तो सरकार के ढीले और सुस्त रवैये की या फिर ऐसे माहिर खिलाड़ियों को आगे लाने वाली संस्थाओं की जो ऐसे खिलाड़ियों को आगे आने के लिए प्रेरित नहीं करती है। सरकार भी जब कोई खिलाड़ी ओलिंपिक या किसी मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उस पर इनाम की बौछार कर देती है। अगर सरकार शुरू से सभी खेलों के खिलाड़ियों की सुविधाओं के प्रति गंभीर रहे तो भारत हर खेल में अव्वल बन जाएगा। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक विद्यार्थियों का खेल में हिस्सा लेना अनिवार्य करे और खेल को पाठ्यक्रम में भी शामिल करे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

ईरान पर अमेरिकी हमले से सोने में उछाल

राजेश भयानी
मुंबई, 3 जनवरी

अमेरिका के हवाई हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मारे जाने के बाद मुंबई के जवेरी बाजार में सोने के दाम 40,000 रुपये के स्तर की ओर बढ़ने लगे हैं। हालांकि दामों में पिछले दो सप्ताह से इजाफा हो रहा है, लेकिन आज दामों में सबसे ज्यादा उछाल आई है क्योंकि कमजोर रुपये से भी सोने के दामों में तेजी को मदद मिली है।

स्टैंडर्ड सोना 39,931 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार के मुकाबले इसमें 873 रुपये या 2.24 प्रतिशत की तेजी आई। अमेरिकी हवाई हमले की खबरों के बाद अंतरराष्ट्रीय दाम भी करीब 1,549 डॉलर प्रति औंस बोले जा रहे थे। डॉलर के मुकाबले रुपये में भी नरमी जारी रही जिससे आयात महंगा हो गया। 26 अगस्त, 2019 के बाद सोने के दामों में आज की उछाल किसी एक दिन की सबसे अधिक उछाल रही। चांदी का भाव 990 रुपये बढ़कर 47,330 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुआ।

पिछले तीन सप्ताह के दौरान मुंबई में सोने के दामों में प्रति 10 ग्राम 2,200 रुपये की तेजी आई है। अब दामों का उतार-चढ़ाव इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान का मसला कैसे जोर पकड़ता है। हालांकि स्थानीय बाजार में दामों की अधिकता के साथ-साथ अशुभ अवधि की वजह से भी मांग को नुकसान पहुंचा है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी का सोने का वायदा भाव पहले ही 40,056 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर पार कर चुका है। जवेरी बाजार के हाजिर बाजार में दाम इससे कम बोले जा रहे हैं क्योंकि अधिक दामों की वजह से मांग में कमी के बाद बाजार में छूट दी जा रही है। हाजिर बाजार में दाम आयात लागत की तुलना में प्रति औंस नौ से 11 डॉलर या प्रति 10 ग्राम 200 से 250 रुपये कम बोले जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप स्वर्ण आयात में भी फौरी तौर पर कमी आई है।

संपत्ति और कीमती धातु के संबंध में खरीद-फरोख्त की अवधि शुभ नहीं होने के कारण 14 जनवरी तक सराफा खरीद कम रहेगी। कई आभूषण विक्रेताओं को आयकर विभाग से कर मांग का नोटिस भी मिला है। यह भी उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दामों में तेजी के कारण पिछले कुछ दिनों से मांग में तीव्र गिरावट आई है और अब तो दाम 40,000 रुपये के स्तर की ओर बढ़ रहे हैं।

जवेरी बाजार के एक प्रमुख जौहरी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि दीवाली से मांग का पूरा परिदृश्य आशावान नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ समय तक ही रहा। पिछली जनवरी के मुकाबले अलग-अलग क्षेत्रों में माग 20 से 30 प्रतिशत कम है।

एक पखवाड़े के बाद अशुभ अवधि समाप्त होने के बाद कुछ जौहरियों को मांग में सुधार होने की उम्मीद है और जनवरी मध्य तक अमेरिका-चीन द्वारा व्यापार समझौते के पहले भाग पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद की जा रही है जिससे सोने के दामों में तेजी रुकेगी और दाम शीर्ष स्तर से नीचे आएंगे। भारत और यूएई में खुदरा शृंखला चलाने वाले पोपली समूह के निदेशक राजीव पोपली ने कहा कि उपभोक्ता यह मान रहे हैं कि सोने के दाम पिछले साल के मुकाबले अधिक स्तर पर बने रहेंगे और इसलिए हमें पोंगल के लिए मांग और संक्रांति (14 जनवरी) के लिए बुकिंग दिख रही है।

स्टैंडर्ड सोना 99.50

दिन	रुपये/10 ग्राम
20 दिसंबर	37,968
23 दिसंबर	38,128
24 दिसंबर	38,291
26 दिसंबर	38,636
27 दिसंबर	38,788
30 दिसंबर	38,822
31 दिसंबर	39,083
1 जनवरी	38,962
2 जनवरी	39,058
3 जनवरी	39,931

स्रोत- आईबीजेए
संकलन- बीएस रिसर्च

देश का स्वर्ण आयात तीन साल के निचले स्तर पर

वर्ष 2019 में देश का स्वर्ण आयात पिछले साल के मुकाबले 12 प्रतिशत गिरकर तीन साल के निचले स्तर पर आ गया है। दूसरी छमाही में स्थानीय दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद खुदरा खरीद कम होने की वजह से ऐसा हुआ है। आज एक सरकारी सूत्र ने यह जानकारी दी।

इस कीमती धातु के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता देश द्वारा कम खरीद के कारण वैश्विक दामों पर असर पड़ सकता है जो वर्ष 2019 में 18 प्रतिशत तक उछल चुके हैं। हालांकि इससे सरकार को व्यापार घाटा कम करने और रुपये को सहारा देने में मदद मिलेगी। भारत सोने की अपनी तकरीबन सारी मांग आयात के जरिये पूरा करता है। सूत्र ने कहा कि वर्ष 2019 में 831 टन सोने का आयात किया गया है, जबकि एक साल पहले 944 टन स्वर्ण आयात किया गया था। इस तरह इसमें गिरावट आई है। सूत्र ने बताया कि मूल्य के हिसाब से वर्ष 2019 में आयात करीब दो प्रतिशत गिरकर 31.22 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल के मुकाबले दिसंबर में स्वर्ण आयात 18 प्रतिशत लुढ़ककर 60 टन रह गया। इस अवधि में मूल्य के हिसाब से स्वर्ण आयात 4.3 प्रतिशत घटकर 2.46 अरब डॉलर रहा। एक निजी बैंक में सराफा अनुभाग के प्रमुख ने कहा, 'हम उम्मीद कर रहे थे कि 2019 की मांग और आयात 2018 से आगे निकल जाएगा। लेकिन जून के बाद से जब दामों में तेजी आने लगी, तो खुदरा मांग कमजोर हो गई।' सितंबर के दौरान भारत में सोने का वायदा भाव प्रति 10 ग्राम 39,885 रुपये के रिकॉर्ड शीर्ष स्तर पर पहुंच गया था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 की पहली छमाही में देश ने 564 टन सोने का आयात किया था, जबकि दूसरी छमाही में आयात 267 टन रहा। आम तौर पर दूसरी छमाही के दौरान आयात में शादी-विवाह के सीजन के साथ-साथ दशहरे और दीवाली जैसे त्योहारों के कारण उछाल आती है। तब सोने की खरीद को शुभ माना जाता है। सराफा आयात करने वाले मुंबई के एक व्यापारी ने कहा कि अगर सराफा के दाम अधिक रहते हैं, तो जनवरी में स्वर्ण आयात गिरकर 40 टन से कम रह सकता है। *रॉयटर्स*

थोक में तेजी से और खुदरा में धीमे घट रहे प्याज के दाम

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 3 जनवरी

- नई फसल की आवक बढ़ने से प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट
- अफगानिस्तान और मिस्र से प्याज के आयात से भी कीमतों में नरमी
- नई आवक के दबाव में इस माह प्याज और सस्ता होने की संभावना

प्याज के दाम रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद अब गिरने लगे हैं। मंडियों में प्याज की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। हालांकि मंडियों में थोक कीमतों की तुलना में खुदरा बाजार में भाव कम नहीं हो रहे हैं। प्याज की कीमतों में गिरावट की वजह नई फसल की आवक बढ़ने के साथ ही आयातित प्याज का आना भी है। कारोबारियों के मुताबिक जनवरी में प्याज की कीमतें और गिर सकती हैं जिससे खुदरा बाजार में भी उपभोक्ताओं को महंगे प्याज से राहत मिलने की संभावना है।

दिल्ली की आजादपुर मंडी में पिछले सप्ताह 20 से 100 रुपये किलो बिकने वाला प्याज अब 20 से 60 रुपये किलो पर आ गया है। मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 20 से 80 रुपये बिकने वाले प्याज के भाव गिरकर अब 15 से 50 रुपये किलो रह गए हैं। लेकिन दिल्ली के खुदरा बाजार में प्याज 90 से 120 रुपये किलो बिक रहा है। खुदरा कीमतों में 10 रुपये किलो की ही गिरावट आई है, जबकि थोक भाव 30 से 40 रुपये किलो गिर चुके हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक एक सप्ताह में प्याज की खुदरा कीमतें दिल्ली में 107 रुपये से गिरकर 86 रुपये, मुंबई में 97 रुपये से 82 रुपये और कोलकाता में 120 रुपये से घटकर 90 रुपये किलो रह गई हैं।

दिल्ली की आजादपुर मंडी स्थित पोटेटो अनियन मर्चेंट एसोसिएशन (पोमा) के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने कहा कि मंडी में पिछले एक सप्ताह में प्याज की कीमतों में लगातार कमी आ रही है। इस कमी की वजह महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से नए प्याज की आवक बढ़ना है। देसी प्याज के अलावा मंडियों में अफगानिस्तान और मिस्र से आयातित प्याज की भी आपूर्ति हो रही है। इससे भी प्याज के दाम घट रहे हैं। मंडी में आयातित प्याज के 10-12 ट्रकों की आपूर्ति हुई। प्याज कारोबारी पीएम शर्मा का कहना है कि नई आवक के दबाव में प्याज सस्ता हो रहा है। आने वाले दिनों में प्याज की आवक और बढ़ने की संभावना है जिससे प्याज के दाम सामान्य की ओर अग्रसर होने की उम्मीद है। कारोबारियों के मुताबिक इस माह खुदरा बाजार में प्याज के दाम 60 से 70 रुपये किलो तक आ सकते हैं।

पिछले साल प्याज उत्पादक क्षेत्रों में असमय बारिश के कारण प्याज की नई फसल लगने में देरी के साथ इसकी फसल को काफी नुकसान हुआ था जिससे लेट खरीफ सीजन में प्याज की पैदावार कम हुई। इस वजह से देश में प्याज के दाम रिकॉर्ड स्तर तक चले गए थे। देश में पहली बार खुदरा बाजार में प्याज 150 रुपये और मंडियों में 100 रुपये से किलो अधिक बिका।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 3	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,772.0	4.4	1,977.5	-1.3
Copper	6,165.5	9.6	6,447.7	6.3
Nickel	14,075.0	-20.9	14,482.9	-19.8
Lead	1,904.0	-9.2	2,172.4	3.4
Tin	17,150.0	4.3	17,825.1	3.2
Zinc	2,299.0	-1.1	2,548.4	-1.8
Gold ($/ounce)	1,543.8*	2.6	1,729.6	4.2
Silver ($/ounce)	18.1*	3.1	20.5	3.7
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	69.1*	19.3	66.0	14.4
Natural Gas ($/mmBtu)	2.1*	-8.8	2.1	-9.7
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	193.1	13.8	307.5	4.4
Maize	187.8*	3.8	329.8	9.2
Sugar	356.9*	4.8	483.5	-1.7
Palm oil	787.5	52.9	1,225.5	44.2
Rubber	1,640.0*	18.0	1,824.3	6.0
Coffee Robusta	1,352.0*	3.0	1,852.1	-6.2
Cotton	1,516.3	13.6	1,603.1	-2.6

* As on Jan 03, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.8& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	77.1	18562
Oil and Oilseeds	333.1	57885
Spices	0.6	13
Metal(Jan 02)		
Metal- non ferrous	4440.3	47016
Metal- precious	12371.4	440
Oil and gas(Jan 02)		
Gas	2917.9	56933
Oil	14818.5	2374

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	181.2	118908
Grains	296.8	104615
Oil and Oilseeds	989.9	554880
Others	212.5	72810
Pulses	117.0	41310
Spices	86.6	29577

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Jan 15)	4104.0	3.3
Nickel (Jan 31)	1044.5	1.5
Silver Micro (Feb 28)	47048.0	0.8
Silver Mini (Feb 28)	47044.0	0.8
Silver (Mar 05)	47022.0	0.8
Gold Mini (Jan 03)	39220.0	0.7
Losers (* % Change)		
Natural Gas (Jan 28)	152.4	-1.7
Crude Oil (Jan 17)	4343.0	-0.8
Kapas (Apr 30)	1119.5	-0.8
Cotton (Jan 31)	19570.0	-0.3
Mentha Oil (Jan 31)	1290.9	-0.2
Lead Mini (Jan 31)	151.8	-0.2

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Jeera Unjha (Jan 20)	16140.0	0.7
Losers (* % Change)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6690.0	-3.7
GuarGum 5T-Jodhpur (Jan 20)	7454.0	-2.8
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6536.0	-2.7
Guar Seed 10 (Jan 20)	4120.0	-2.1
CottonSeed Oil-Akola (Jan 20)	2139.0	-1.3
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1120.0	-1.0
Chana-Bikaner (Jan 20)	4498.0	-0.8
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4614.0	-0.7
Soyabean Indore (Jan 20)	4358.0	-0.7
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	937.6	-0.5
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4210.0	-0.1

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	4104.0	9.7
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19570.0	2.9
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	1.3
Nickel Mumbai (Jan 31)	1044.5	0.7
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1290.9	-8.5
Alumini-Mumbai (Jan 31)	137.7	-3.0
Lead Min Mumbai (Jan 31)	151.8	-2.4
Gold Petal-Mumbai (Jan 31)	3919.0	-2.0
Copper Mum (Jan 31)	443.8	-1.7
Gold Ahm (Feb 05)	39277.0	-1.7
Aluminium Mum (May 29)	139.6	-1.7
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	180.6	-1.6

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6536.0	4.5
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	837.1	1.2
Bajra-Delhi (Jan 20)	2047.0	0.7
Bajra-Jaipur (Jan 20)	2047.0	0.6
Barley Jaipur (Jan 20)	2200.5	0.4
Discount over spot price (In %)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6690.0	-4.8
Soy Bean Indore (Jan 20)	4358.0	-3.5
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Jan 20)	7454.0	-2.6
Moong-Merta City (Jan 20)	7396.0	-2.3
Paddy-Basmati-Karnal (Jan 20)	3259.0	-1.2
Jeera Unjha (Jan 20)	16140.0	-0.5

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	106.....(104)
Aluminium ingots /kg	142.....(140)
Brass sheet cutting /kg	328.....(328)
Brass utensil scraps/kg	312.....(312)
Copper heavy scrap /kg	431.....(431)
Copper utensil scraps/kg	402.....(402)
Copper wire bar /kg	463.....(464)
Lead ingots /kg	156.....(157)
Nickel Cathodes /kg	1040.....(1050)
Tin slabs /kg	1280.....(1265)
Zinc slabs /kg	183.....(184)
Source:Bombay Metal Exchange	
Cotton	**Mumbai**
Bengal Deshi /Qtl	10320.....(10320)
DCH - 32 /Qtl	11276.....(11248)
Jaydhar /Qtl	9926.....(9926)
Shankar- 6 /Qtl	11079.....(11051)
Source:Cotton Association of India	
Oil	**Mumbai**
Castor FSG /10kg	894.....(895)
Castor Comm /10kg	884.....(885)
Ricebran oil/10kg	820.....(820)
Groundnut oil /10kg	1180.....(1180)
Linseed oil /10kg	990.....(1000)
Karanji /10kg	800.....(800)
Palm oil /10kg	882.....(878)
Sunflower exp ref /10kg	940.....(940)
Sunflower oil exp /10kg	900.....(895)
Soyabean ref / 10kg	935.....(935)
Source:Bombay Commodity Exchange	

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3362-3582.....(3352-3582)
Source:Bombay Sugar Merchants Association	

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	63.71.....(61.18)
Brent Crude (UK)	69.51.....(66.62)
Brent Crude (WTI)	61.18.....(61.18)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.11.....(2.12)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	321.79.....(299.17)
Naptha spot /Rs/MT	45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.....(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com	

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	39931.....(39058)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40092.....(39215)
Silver.999/ kg	47330.....(46340)
Source:India Bullion & Jewellers Association	

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18883.60	18949.30
Alumini-Mumbai (M)	1 K	143.35	141.90
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2050.00	2032.50
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	2042.25	2035.75
Barley Jaipur (N)	1 Q	2194.05	2191.90
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4302.50	4294.10
Castor Seed-Kadi (N)	X	4250.00	4232.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4448.00	4413.35
Chana Delhi (N)	1 Q	4666.20	4650.00
Chana-Akola (N)	X	4512.50	4512.50
Coriander-Gondal (N)	X	6728.00	6733.00
Coriander-Jaipur (N)	X	7000.00	7000.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	7106.50	7025.75
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2200.00	2173.55
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2176.25	2160.40
Cotton-Kadi (N)	1 B	18883.60	18943.35
CPO-Kandla (M)	10 K	811.00	810.50
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	833.40	827.15
Gold Ahm (M)	10 G	39068.00	39948.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	31380.00	32087.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3917.00	4001.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7754.25	7652.10
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4146.90	4101.25
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1250.70	1142.35
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16950.00	17000.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16243.50	16216.65
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1055.65	1055.65
Kapas-Rajkot (N)	X	1056.90	1054.90
Lead Mum (M)	1 K	155.50	155.50
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2040.00	2040.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2436.35	2443.90
Maize-Erode (N)	X	2082.20	2064.15
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2250.00	2255.00
Maize-Sangli (N)	X	2000.20	2013.65
Moong-Merta City (N)	1 Q	7593.75	7568.75
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4861.90	4829.70
Nickel Mumbai (M)	1 K	1051.70	1037.50
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3250.00	3300.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35000.00	35000.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2100.00	2075.00
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	872.50	880.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	942.70	937.80
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	942.60	936.55
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	959.00	956.25
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13100.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46257.00	47307.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4567.00	4516.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4472.25	4370.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4582.90	4494.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4523.00	4456.00
Soymeal Indore (N)	1 T	36525.00	36000.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3265.00	3255.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3371.45	3374.10
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3265.00	3272.50
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3457.15	3471.45
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3310.00	3300.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3105.00	3120.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6273.90	6256.50
Wheat Delhi (N)	1 Q	2353.35	2358.35
Wheat Kota (N)	1 Q	2248.90	2257.50
Wheat New Indore (N)	1 Q	2300.00	2310.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2185.00	2190.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2310.00	2325.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5750.00	5700.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	184.00	183.50

* as on Jan 02, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (शुक्रवार)

कृषि जिंस

Cotton

Cotton MCX(1 B)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 31	19670, 19740, 19560, 19570	5901	731	15383
Feb 28	19920, 19990, 19830, 19870	625	114	2194
Mar 31	20210, 20210, 20210, 20210	04	1	85

CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 20	2169, 2186, 2132, 2139	28310	2169	44550
Feb 20	2190, 2207, 2155, 2162	32870	2417	61220
Mar 20	2215, 2229, 2179, 2185	3140	262	7000
Apr 20	2240, 2248, 2210, 2213	1030	81	1780

Kapas MCX(20 K)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Apr 30	1136, 1136.5, 1118, 1119.5	268	61	884

Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Apr 30	1136.5, 1139, 1118, 1120	1738	927	4358

Grains

Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 20	4224, 4234, 4100, 4120	30065	3891	44560
Feb 20	4268, 4278, 4150, 4166	40315	4896	57210
Mar 20	4316, 4316, 4200, 4204	375	48	585

Oil and Oilseeds

CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 20	4220, 4224, 4188, 4210	2665	284	20355
Feb 20	4234, 4248, 4212, 4232	1835	190	16160
Mar 20	4190, 4214, 4190, 4206	100	17	6880
Apr 20	4200, 4230, 4200, 4230	50	9	1935

Crude Palm Oil MCX(10 K)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 31	822.1, 823.5, 808.6, 817.4	27870	1869	39290
Feb 28	825, 825, 811, 818.9	9610	712	17520
Mar 31	818.6, 818.6, 808, 813.8	40	4	820

Mentha Oil MCX(1 K)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 31	1291.2, 1301, 1288, 1290.9	184.32	395	234.72
Feb 28	1307.7, 1311.7, 1299.2, 1300	22.32	48	19.08

Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 20	4657, 4664, 4607, 4614	11490	961	14510
Feb 20	4656, 4677, 4611, 4616	7720	632	8930
Apr 20	4558, 4574, 4502, 4511	5110	389	11400
May 20	4530, 4530, 4506, 4506	40	4	810

Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 20	944, 944.4, 932, 937.6	15380	1819	31550
Feb 20	942.8, 942.8, 930.4, 935.8	23715	2494	53455
Mar 20	937, 937, 924.6, 930.2	1850	238	23255
Apr 20	930.2, 930.2, 918.2, 923.8	105	13	2360

Soyabean Indore NCDEX(1 Q)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 20	4392, 4394, 4334, 4358	39145	4498	84850
Feb 20	4410, 4420, 4356, 4382	55915	6196	178185
Mar 20	4414, 4440, 4380, 4402	10180	1218	85030
Apr 20	4430, 4466, 4416, 4438	2430	318	14060
May 20	4490, 4490, 4480, 4490	395	33	1135

Others

GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 20	7689, 7714, 7437, 7454	10275	1411	17440
Feb 20	7790, 7810, 7531, 7546	16430	2206	52500
Mar 20	7885, 7908, 7660, 7666	1115	155	2870

Pulses

Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 20	4530, 4563, 4490, 4498	15950	1223	25370
Mar 20	4458, 4504, 4446, 4455	9340	705	14880
Apr 20	4480, 4480, 4440, 4462	700	27	950

Spices

Cardamom MCX(1 K)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 15	4076.9, 4130, 4076.9, 4104	0.7	7	6.1
Feb 14	3941.6, 3979.8, 3941.6, 3974.3	0.7	7	5.8

Coriander-Kota NCDEX(1 Q)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 20	6966, 7015, 6671, 6690	3350	307	7600
Apr 20	7340, 7370, 7081, 7113	2850	261	7950
May 20	7325, 7325, 7140, 7140	120	12	180

Jeera Unjha NCDEX(1 Q)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 20	16065, 16180, 15990, 16140	534	174	1434
Mar 20	15615, 15685, 15570, 15640	423	132	1173
Apr 20	15370, 15390, 15320, 15355	96	30	450

Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Mar 20	6760, 6784, 6506, 6536	2975	527	6295
Apr 20	6640, 6648, 6418, 6440	875	166	4455
May 20	6572, 6572, 6500, 6500	25	5	40

धातु

Metal- non ferrous

Aluminium MCX(1 K)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
May 29	142.6, 142.6, 142.6, 142.6	1	1	1

Aluminium Mini MCX(1 K)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 31	137.85, 138.1, 137.55, 137.65	3157	2086	6122
Feb 28	137.4, 137.7, 137.2, 137.35	125	116	911

Copper MCX(1 K)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 31	442.85, 444.15, 439.25, 439.7	16092.5	5434	12775
Feb 28	446.9, 447.9, 443.4, 443.75	362.5	144	725

Lead MCX(1 K)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
May 29	147, 157.1, 147, 152.3	25	8	1

Lead Mini MCX(1 K)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 31	151.75, 151.95, 151.4, 151.5	3962	2600	6120
Feb 28	152, 152.15, 151.55, 151.75	91	88	287

Nickel MCX(1 K)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 31	1041, 1041, 1022.5, 1024.7	13032	7488	2725.5
Feb 28	1024, 1031.8, 1022.5, 1

अमेरिका-ईरान तनाव से तेल में ताप

ईरान पर अमेरिकी हमले से पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनने लगी है और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा

शाइन जैकब

अमेरिकी हमले में ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 4.4 फीसदी की तेजी आई और यह शुक्रवार को 69.16 डॉलर प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। यह अमेरिकी हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब इस वित्त वर्ष में देश के बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अब तक औसतन 64 डॉलर प्रति बैरल रही हैं। ऐसे में देश में कच्चे तेल के आयात बिल में बढ़ोतरी की आशंका है और यह 7.84 लाख करोड़ रुपये के पहले के लक्ष्य के मुकाबले ज्यादा हो सकता जो 2018-19 की तुलना में मामूली रूप से 0.15 फीसदी अधिक है।

शुक्रवार को देश में कच्चे तेल की कीमत 65.99 डॉलर प्रति बैरल थी। हालांकि पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण होने की स्थिति में कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार के ताजा अनुमान के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतों में 1 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी भी होती है तब देश के आयात बिल में बढ़ोतरी 6,328 करोड़ रुपये तक होगी। इसके अलावा एक डॉलर के मूल्य में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी होती है तब विनिमय दर बढ़ने से कच्चा तेल आयात बिल में करीब 5,883 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तेजी देखी जाएगी। इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉरपोरेट रेटिंग्स) के रविचंद्रन ने कहा है, 'अगले दो हफ्ते बाजार में तनाव दिखेगा। अगर संकट की स्थिति बनी रही तब कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनी रहेगी और कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।' उनका कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से व्यापार घाटा और उन तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) पर असर पड़ सकता है जो घाटे में हैं। विशेषज्ञों ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं और इससे महंगाई बढ़ सकती है।

शुक्रवार को अमेरिकी हवाई हमले के बाद बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर जलता वाहन

आर्थिक गतिविधियां कम होने की वजह से कई सालों के बाद पहली बार देश में कच्चे तेल की मांग में कमी दिख रही थी क्योंकि इस साल अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान आयात में 0.7 फीसदी की गिरावट आई और यह 14.9 करोड़ टन हो गया जो 2018-19 की इसी समान अवधि के दौरान 15.1 करोड़ टन था। कच्चे तेल के आयात बिल में 11.6 फीसदी की बड़ी गिरावट देखी गई और यह इस साल अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान 69.5 अरब डॉलर हो गया जो पिछले साल 78.6 अरब डॉलर था।

डेलॉयट टच तोमैटसू में पार्टनर देवाशिष मिश्रा कहते हैं, 'हम अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85 फीसदी हिस्सा आयात कर रहे हैं ऐसे में फारस की खाड़ी में अस्थिरता, देश के लिए कीमतों में अस्थिरता और आपूर्ति सुरक्षा की दृष्टि के लिहाज से अच्छी नहीं है। हालांकि मंदी वाले साल के बाद 2020 में वैश्विक कच्चे तेल की मांग में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं।'

ऑयल ऐंड नैचुररल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ओएनजीसी विदेश का कोई भी अधिकारी इन तनावग्रस्त देशों में नहीं फंसे हैं। अमेरिका ने अपने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के निर्देश पर शुक्रवार को सुबह बगदाद के हवाई अड्डे पर हमला किया। इस हमले में ईरान जनरल सुलेमानी के सलाहकार और कमांडर अबु महदी अल-मुहांदिस भी मारे गए। सुलेमानी ईरान के शीर्ष जनरल थे। इस बात को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ईरान इसकी प्रतिक्रिया में हमला कर सकता है ऐसे में अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा है।

उद्योग के दूसरे विशेषज्ञ के मुताबिक इसका दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग पर असर पड़ सकता है जो इस साल की छमाही तक बढ़ने की उम्मीद थी। इस साल नवंबर तक देश का कुल आयात बिल 318.8 अरब डॉलर तक था जिनमें से पेट्रोलियम आयात करीब 25.4 फीसदी तक था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम एशिया से इस वित्तीय वर्ष में सितंबर तक भारत ने 6.4 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया।

तेल की कीमतों से संकट

- ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में **4.4** फीसदी की तेजी आई और यह शुक्रवार को **69.16** डॉलर प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया
- पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से कच्चे तेल के आयात बिल में बढ़ोतरी की आशंका
- आयात बिल **7.84** लाख करोड़ रुपये के पहले के लक्ष्य के मुकाबले अधिक हो सकता है

107 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी पीटीआई

देश के निर्माण में अहम है तकनीक

युवराज मलिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वैज्ञानिकों तथा विज्ञान समुदाय को ग्रामीण, गरीबों तथा किसानों के लिए नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए हालांकि इससे संबंधित काम में विवेक का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बेंगलूरु स्थित कृषि विश्वविद्यालय में 107 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर मोदी ने कहा, 'न्यू इंडिया को प्रौद्योगिकी के साथ ही एक तार्किक स्वभाव की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए हमारे प्रयास सही दिशा में हो।'

एक दिन पहले मोदी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की पांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया था जिनमें केवल 35 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को रखा जाएगा तथा वे आधुनिक तकनीकों पर काम करेंगे। वैज्ञानिकों तथा छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीक के अहम भूमिका का निर्वहन किया है।

आधार संबंधी लाभ, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छता तथा गरीबों के लिए घर जैसी अनेक योजनाओं में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने आग्रह किया, 'साथियों, हमें कृषि में योगदान करने वाली प्रौद्योगिकी क्रांति की आवश्यकता है। आपके योगदान से भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।' मोदी ने कहा कि अगला दशक ग्रामीण तकनीक, विशेषकर सस्ती कृषि तथा खेत से उपभोक्ता तक की आपूर्ति शृंखला के लिए निर्णायक होगा, जहां प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण सुधार लाएगी।

उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं, ई-कॉमर्स और मोबाइल बैंकिंग ने ग्रामीण आबादी को काफी मदद की है, जबकि आधार आने के बाद से आधुनिक डेटा साइंस ने परियोजनाओं को बेहतर ढंग से लाक्षित करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी ने सरकार को लालटेन तथा चूल्हे के धुएं से परेशान रहने वालीं 8 करोड़ महिलाओं की पहचान करने में मदद की और उनके घरों तक बिजली पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवा वैज्ञानिकों से 'नवोन्मेष, पेटेंट, निर्माण और समृद्धि' की दिशा में आगे बढ़ने की अपील करते हुए कहा कि ये कदम देश को विकास की तरफ ले जाएंगे। *(साथ में एजेंसियां)*

विमानन कंपनियां भी परेशान...

अनीश फडणीस

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और धीमी मांग से घरेलू विमानन कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की तेल विपणन कंपनियों ने एक जनवरी से जेट ईंधन की कीमतों में 2.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। फिलहाल जेट ईंधन के एक किलोलीटर की कीमत 64,423 रुपये है और ये कीमतें सालाना आधार पर 10 प्रतिशत अधिक हैं।

ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ने के बाद शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में चार प्रतिशत का इजाफा हुआ है और तेल उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती तथा चीन-अमेरिका के मध्य व्यापार समझौते की उम्मीद से इन कीमतों में तेजी बने रहने की उम्मीद है। हालांकि नरम मांग के चलते विमानन कंपनियां तेल कीमतों में आई तेजी को ग्राहकों पर हस्तांतरित नहीं कर सकतीं। क्लियरट्रिपडॉटकॉम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालू रामचंद्रन कहते हैं, 'हमने देखा है कि जनवरी 2020 में यात्रा का किराया सालाना आधार पर चार प्रतिशत अधिक है। अप्रैल से दिसंबर के बीच औसत किराए में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और हमें उम्मीद है कि जनवरी माह में किराए में तेजी रहेगी।' जनवरी-नवंबर के बीच घरेलू हवाई यातायात 3.8 प्रतिशत बढ़ा है और केवल नवंबर महीने में दो अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। रामचंद्रन ने कहा, 'वर्तमान कीमतों के हिसाब से मांग नरम बनी हुई है।' एफसीएम ट्रैवल सॉल्यूशंस के प्रबंध निदेशक रक्षित देसाई कहते हैं, 'मेरे विचार से विमानन कंपनियों के लिए एग्जीक्यूटिव किराए में बढ़ोतरी करना मुश्किल होगा क्योंकि बाजार कीमतों के लिहाज से संवेदनशील है। साथ ही, गर्मियों के लिए एडवांस बुकिंग भी कम है।'

जेट ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से विमानन कंपनियों की मुश्किलें बढ़ी

इक्रा रेटिंग्स में उपाध्यक्ष तथा सह-प्रमुख (कॉर्पोरेट सेक्टर रेटिंग) किंजिल शाह कहती हैं, 'अधिकांश विमानन कंपनियों ने लोड फैक्टर में सुधार तथा कार्यशील पूंजी की स्थिति में सुधार के लिए मूल्य निर्धारण में लगी हुई हैं। इसके चलते पूरे उद्योग में छूट देने की होड़ चल रही है। उम्मीद है कि निकट अवधि में हवाई किराए पर दबाव जारी रहेगा।'

भारतीय विमानन कंपनियों के कुल परिचालन लागत में तेल की हिस्सेदारी 35-40 प्रतिशत होती है। इसके अलावा डॉलर की कीमतें भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। क्रिसिल रिसर्च की निदेशक हेतल गांधी कहती हैं, 'कच्चे तेल की कीमतों में एक डॉलर का इजाफा होने से परिचालन लागत में 50-60 आधार अंकों की बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में एक रुपये की कमजोरी आने पर लागत में 900-1000 आधार अंकों की बढ़ोतरी हो जाती है।'

'तनाव से दुनिया चौकन्नी'

अमेरिकी हमले में ईरान के एक शीर्ष कमांडर के मारे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने शुक्रवार को कहा कि तनाव बढ़ने की वजह से दुनिया चौकन्नी हो गई है। इसके साथ ही भारत ने जोर दिया कि उसके लिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा महत्त्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने लगातार संयम पर जोर दिया है और यह अहम है कि हालात और खराब नहीं हो।

अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने घोषणा की थी कि इराक में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'तनाव बढ़ने से दुनिया चौकन्नी हो गई है। इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता महत्त्वपूर्ण है।'

आंकड़ों की जुबानी, 2019 की कहानी

रोमिता मजूमदार

इस साल विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देश के चुनाव, पड़ोसी देशों से झड़प और आंतरिक टकराव पर चर्चा होती रही और राजनीतिक विचारकों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। अधिकांश रिपोर्ट या सूची दिसंबर महीने से पहले ही तैयार की जा चुकी थीं जिसके चलते इनमें सीएए पर संवाद तथा देश के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट बंद करने पर चर्चा को शामिल नहीं किया जा सका।

हालांकि ये सभी सूची पढ़ने पर हमें इस बात की झलक मिलेगी कि आखिर हम क्या हैं और बाजार किस तरह से डेटा चार्ट का इस्तेमाल कर रहा है। हाइपर कलेक्टिव के संस्थापक एवं चीफ क्रिएटिव ऑफिसर केवी श्रीधर कहते हैं, 'हमेशा कुछ सूचियों को देखें और उन पर भरोसा करने से पहले उनकी डेटा प्रामाणिकता तथा तीसरे पक्ष के सत्यापन के अनुसार जांच करें।'

इन सूचियों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए जितना इन्हें तथा दूसरे शोध के मानकों को लिया जाता है। हालांकि ये ग्राहक की सोच की एक छवि प्रस्तुत कर देती हैं और लोकप्रियता के पायदान पर आने वालों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। कभी कभार इन्हें पढ़ना शिक्षाप्रद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, सर्वाधिक देखी गई लोकप्रिय फिल्में या हैशटैग तथा पोस्ट ने सोशल प्लेटफॉर्म पर राजनीति, पितृसत्ता तथा पौरुष आदि पर वृहद चर्चा शुरू की। कबीर सिंह जैसी फिल्म ने पौरुषत्व पर गंभीर बहस छेड़ दी तो वहीं जोमैटो तथा एयरटेल कंपनियों को धार्मिक तथा राष्ट्रवादी बहसों में शामिल किया गया।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शीर्ष ट्रेंड :

- लोकसभा चुनाव 2019
- अनुच्छेद 370
- पुलवामा हमला
- चंद्रयान-2
- आईसीसी क्रिकेट विश्व कप
- अयोध्या पर फैसला
- कबीर सिंह

ट्विटर ट्रेंड

1. #लोकसभाइलेक्शन2019 पर सबसे अधिक चर्चाएं हुईं
2. #चंद्रयान2, इसरो की सराहना करते हुए नासा का एक ट्वीट भारतीयों द्वारा इस साल के शीर्ष दस सबसे अधिक रीट्वीट किए गए ट्वीट में से एक रहा
3. #सीडब्ल्यूसी19, गेम एनालिसिस से लेकर वायरल मीम तक, यह हैशटैग सभी जगह शामिल था
4. #पुलवामा, 40 सीआरपीएफ कर्मियों के शहीद होने से देश में चर्चा का माहौल
5. #अनुच्छेद370, अगस्त 2019 में सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया। इसे ट्विटर पर काफी समर्थन तथा विरोध, दोनों तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली

सबसे अधिक खोज

गूगल पर

1. क्रिकेट विश्व कप
2. लोकसभा चुनाव
3. चंद्रयान-2
4. कबीर सिंह
5. अवेंजर्सः एंडगेम

शेयरचैट पर

1. चुनाव 2019
2. पुलवामा हमला, शहीदों को नमन
3. अभिनंदन वर्धमान

खबरों में व्यक्ति

गूगल पर

1. अभिनंदन वर्धमान
2. लता मंगेशकर
3. युवराज सिंह
4. आनंद कुमार
5. विकी कौशल

टिकटॉक पर

1. जैकलिन फर्नांडिस
2. रितेश देशमुख
3. कपिल शर्मा
4. माधुरी दीक्षित
5. डीजे ब्रावो

ट्विटर पर (पुरुष)

1. अमिताभ बच्चन
2. अक्षय कुमार
3. सलमान खान
4. शाहरुख खान
5. विजय

(महिलाएं)

1. सोनाक्षी सिन्हा
2. अनुष्का शर्मा
3. लता मंगेशकर
4. अर्चना कल्पनाथी
5. प्रियंका चोपड़ा जोनस

सर्वाधिक देखा गया...

बुक माय शो-शीर्ष पांच

1. अवेंजर्सः एंडगेम
2. उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक
3. कबीर सिंह
4. साहो
5. वॉर

आईएमडीबी-शीर्ष पांच वेब सीरीज

1. कोटा फैक्ट्री (यूट्यूब/टीवीएफ)
2. सेक्रेड गेम्स (नेटफ्लिक्स)
3. द फैमिली मैन (एमेजॉन प्राइम वीडियो)
4. दिल्ली क्राइम (नेटफ्लिक्स)
5. ह्यूमरसली योर्स (यूट्यूब/टीवीएफ प्ले)

विज्ञापन फ्री प्राइम वीडियो में ब्रांडों की सेंध

सोहिनी दास

विभिन्न ब्रांड काफी समय से सबस्क्रिप्शन आधारित ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ कारोबार करने की योजना बना रहे हैं। एक तरफ एमेजॉन प्राइम के भारत में 20 लाख से अधिक सबस्क्राइबर हैं तो वहीं नेटफ्लिक्स के 12 लाख से अधिक सबस्क्राइबर। इस संख्या ने इन दोनों प्लेटफॉर्म को बाजार के लिए काफी अहम बना दिया है और ये प्लेटफॉर्म भी विज्ञापन नहीं दिखाने के अपने वादे को निभाने के साथ साथ राजस्व के आंकड़े बढ़ाने के लिए ब्रांड के साथ भी काम कर रहे हैं।

इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एमेजॉन प्राइम ने अपने लोकप्रिय शो 'इनसाइड ऐज' के दरवाजे ब्रांड के लिए खोल दिए हैं। ऑडियो सामान निर्माता जेबीएल और स्नैक्स उपलब्ध कराने वाली टू यमी को इस शो की कहानी में शामिल किया गया है। नेटफ्लिक्स भी वैश्विक स्तर पर अपनी सीरीज स्ट्रेंज थिंग्स, ग्रीन ऐग ऐंड हैम और दूसरे कई शो के साथ ऐसे प्रयोग कर रही है।

एमेजॉन प्राइम के देश में 20 लाख से अधिक सबस्क्राइबर

एमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया के निदेशक और महानिदेशक (भारत) गौरव गांधी का कहना है कि वे सहायक ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। इस तरह के कदम से ब्रांड को दर्शकों की बड़ी संख्या के बीच जाने में मदद मिलती है। ओटीटी कंपनियों को इससे अपनी ओरीजिनल सामग्री के लिए आर्थिक मदद मिलती है और उन्हें कहानी के बीच में विज्ञापन भी नहीं देने पड़ते।

भारतीय बाजार में सबस्क्रिप्शन दरें काफी कम हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म विभिन्न ब्रांड के साथ अधिक कारगर एवं नियमित जुड़ाव के इच्छुक हैं। इस कदम से करीब 30 करोड़ दर्शकों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हॉटस्टार से मिल रही प्रतिस्पर्धा से निपटने का तरीका भी है। हालांकि हॉटस्टार एक अलग मॉडल अपनाती है। मुफ्त में देखे जाने वाले वीडियो के लिए पारंपरिक विज्ञापन और वीडियो के बीच में आने वाले विज्ञापन हैं और केवल प्रीमियम सदस्यता वाली सेवा के लिए ही विज्ञापन मुक्त वीडियो सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

नए क्षेत्रों में निवेश पर मुरुगप्पा का जोर

पृष्ठ-1 का शेष

अरुणाचलम ने कहा कि वह विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के तैयार थी। उन्होंने कहा, 'सौदा करने का हमेशा एक उचित तरीका हो सकता है और हमने यह भी नहीं कहा कि हमारे किसी भी लेनदेन का भुगतान एकमुश्त कर दिया जाए।' अरुणाचलम ने कहा कि उनके पिता की इच्छा थी कि सभी परिसंपत्ति वितरण सदभाव पूर्ण तरीके से किया जाए, लेकिन दो वर्ष बीतने के बाद उन्हें लग रहा है कि वे सभी विकल्प दूर हाथ से निकल रहे हैं, जिनसे उन्हें खुशी (पिता) मिल सकती थी। उन्होंने कहा, 'मैं यथार्थवादी हूं, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो मुझे दूसरे उपलब्ध विकल्पों पर विचार करना होगा।' अरुणाचल ने कहा कि जब उनके पिता जीवित थे तो उन्होंने परिवार का पूरा साथ दिया और सदस्यों को सभी तरह से मदद की। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि उनके योगदानों को इस समय कोई याद करने के लिए तैयार नहीं है।

वी सुबैया और एमए अलगप्पन ने इस बारे में उन्हें भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। मुरुगप्पा समूह के अधिकारियों ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यह मामला परिवार और परिवार से जुड़ी निवेश कंपनी से जुड़ा है। मुरुगप्पा के मौजूदा संरक्षक सुबैया समूह के कार्यकारी चेयरमैन रह चुके हैं। अलगप्पन भी समूह के कार्यकारी चेयरमैन रह चुके हैं और उन्होंने 2009 में यह पद छोड़ा था। सवाल यह है कि अगर अरुणाचलम पुरुष होती तो क्या स्थिति अलग होती? अरुणाचलम को ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि परिवार के मौजूदा प्रमुख एमवी सुबैया ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि परिवार ने कभी भी महिला सदस्यों को कारोबार में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी है।

कई सफल पारिवारिक कारोबारी समूहों की तरह मुरुगप्पा समूह ने भी भविष्य की तैयारी के लिए स्वामित्व को परिचालन प्रबंधन की भूमिका से अलग किया है। इनमें पेशेवर मैनेजरों और गैर पारिवारिक निदेशकों को कॉरपोरेट बोर्ड में शामिल करना शामिल है। साथ ही समूह में भविष्य के मद्देनजर अपने कारोबार के पोर्टफोलियो में भी बदलाव किया है।

हालांकि समूह की कई कंपनियां कम मुनाफा दे रही हैं लेकिन उसका जोर नए क्षेत्रों में निवेश और मौजूदा कारोबार के विस्तार पर है। 2018 में कंपन ने रूस में एक गैस संयंत्र पर 2,000 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की थी।

इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज (आईआईएएस) के प्रबंध निदेशक अमित टंडन ने कहा कि कई प्रवर्तकों वाले किसी भी बड़े कारोबारी समूह के लिए प्रबंधन की व्यवस्था में बदलाव आसान नहीं है। हालांकि कारोबार के बदलते समीकरणों के मद्देनजर इसकी समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि ऐसा सर्वसम्मति से होना चाहिए। पिछले दशक में कंपनियों और कॉरपोरेट समूहों में एक बड़ा बदलाव यह रहा कि महिलाओं की संख्या पहले से बढ़ गई।